NYCS

RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com

अगस्त 2026, नई दिल्ली

एनसीडीसी छू रहा नई ऊंचाइयां

अंदर के पन्नों पर

- हुनर से आत्मनिर्भरता तक, युवाओं के भविष्य को संवारती एनवाईसीएस की कौशल विकास पहल
- श्वेत क्रांति की धरती से शुरू हुई सहकारी शिक्षा की नई क्रांति

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत-किसान बने खुशहाल

नैनो यूरिया प्लस • नैनो डीएपी • नैनो एनपीके
नैनो ज़िंक • नैनो कॉपर • धरामृत • सागरिका • जैव उर्वरक

उत्तम खेती के लिए स्मार्ट समाधान

मिट्टी की उर्वरता बढ़े
पर्यावरण के लिए सुरक्षित
कम मात्रा में अधिक प्रभाव

इफको का है यह अभियान,
स्वस्थ हो धरती, खुशहाल बने किसान

कम लागत में अधिक उत्पादन
फसल की गुणवत्ता में सुधार
भंडारण एवं प्रयोग करने में आसान

नैनो उर्वरक अपनाओ, फसलों का उत्पादन, गुणवत्ता और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाओ।

इफको के नैनो उर्वरक सम्पूर्ण स्वदेशी हैं | इफको द्वारा विकसित नैनो उर्वरक, आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर कृषि की पहचान हैं

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली - 110017
दूरभाष: 91-11-26510001, 91-11-42592626 | **वेबसाइट:** www.iffco.in
ग्राहक सेवा हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री): 1800 103 1967

इफको के उत्पाद और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें और हमसे जुड़ें

युवा सहकार

वर्ष : 03, अंक-02, अगस्त-2026

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता
दर्शन सोलंकी (विशेष आमंत्रित)
देवेन्द्र सिंह (विशेष आमंत्रित)
रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी (सीईओ)

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं फर्स्ट इंप्रेशन कॉरपोरेट सर्विस प्रा. लि., सेक्टर-63, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी द्वारा मुद्रित।

कार्यकारी संपादकः अभिषेक कुमार
पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

आर्थिक रूप से सशक्त हो रही सहकारिता 04
किसानों के बच्चों को स्कॉलरशिप देगा नेफेड 05

06 एनसीडीसी छू रहा नई ऊंचाइयां

12 सहकार भारती का बजा डंका

अमूल बंगाल में लगाएगी सबसे बड़ा दही प्लांट 14
सहकार की सवारी, समृद्धि की तैयारी 20
कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट 29 देशों तक पहुंचा 23
श्वेत क्रांति की धरती से शुरू हुई सहकारी शिक्षा की नई क्रांति 24
भविष्य उन्हीं का है जो सीखते हैं, बदलते हैं और नवाचार करते हैं 26
तृतीय चिनार पुस्तक महोत्सव में दिखा साहित्य, संवाद और युवा हिस्सेदारी का संगम 28
बिहार बनेगा ग्लोबल स्किल हब 30
हॉकी टीम की केसरिया जर्सी का विवाद बेवजह 32
गोबर से स्वच्छ ऊर्जा बनाने को एमसीडी-एनडीबीबी में एमओयू 34

आर्थिक रूप से सशक्त हो रही सहकारिता

सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं ने भी एनसीडीसी में हुए परिवर्तन को नई गति दी है। युवा सहकार, आयुष्मान सहकार, डेयरी सहकार, डिजिटल सहकार, स्वयं शक्ति सहकार और नंदिनी सहकार जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, डेयरी उद्यमियों, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल नवाचारों को वित्तीय सहायता मिल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

सहकारिता क्षेत्र से जुड़े मेरे प्रिय साथियों, आपकी मनपसंद पत्रिका युवा सहकार एक बार फिर से आपके सामने है। कुछ वजहों से पिछले चार महीने से आपकी इस प्रिय पत्रिका का प्रकाशन नहीं हो पा रहा था। कभी-कभी ऐसी समस्याएं आती है जिसकी वजह से बेमन से फैसले लेने पड़ते हैं। मगर अब उन समस्याओं का निवारण हो गया है। अगस्त महीने से लगातार यह पत्रिका आपको मिलती रहेगी जिनमें सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां और जानकारियां आपको पहले की तरह दी जाती रहेंगी।

जैसा कि हमारे सहकार बंधु जानते हैं कि भारतीय सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उस राह में निगम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस दौरान एनसीडीसी ने 1.55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्तीय सहायता सहकारी समितियों के लिए स्वीकृत की जिनमें से 1.27 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज वितरित किया। निगम का यह अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक वितरण है। इसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 95.182 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 2014-15 में एनसीडीसी का ऋण वितरण केवल 5,735 करोड़ रुपये था।

एनसीडीसी के वित्तीय समर्थन का लाभ न सिर्फ सहकारी समितियों को मिल रहा है, बल्कि इससे इन समितियों में रोजगार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। रिकॉर्ड ऋण वितरण, मजबूत वित्तीय अनुशासन और नई योजनाओं के माध्यम से एनसीडीसी ने यह साबित किया है कि सहकारिता देश के समावेशी आर्थिक विकास की सबसे प्रभावी ताकत बन सकती है। भारतीय सहकारिता आंदोलन आज केवल किसानों को सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला एक मजबूत विकास मॉडल बन चुका है।

सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं ने भी एनसीडीसी में हुए परिवर्तन को नई गति दी है। युवा सहकार, आयुष्मान सहकार, डेयरी सहकार, डिजिटल सहकार, स्वयं शक्ति सहकार और नंदिनी सहकार जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, डेयरी उद्यमियों, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल नवाचारों को वित्तीय सहायता मिल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का वित्तीय कारोबारी दायरा समूचे सहकारी आर्थिक तंत्र में फैला हुआ है। कृषि विपणन के साथ कृषि इनपुट में शामिल कृषि-प्रसंस्करण, चीनी, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, अन्न भंडारण और कोल्ड चेन, क्रेडिट और सेवा सहकारी समितियां, एफपीओ, निर्यात संवर्धन और कमजोर वर्ग की सहकारी समितियों को वित्तीय मदद उपलब्ध करा कर उन्हें सशक्त बनाने का जो काम एनसीडीसी कर रही है वह विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी। ■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

किसानों के बच्चों को स्कॉलरशिप देगा नेफेड

युवा सहकार टीम

देश के किसान परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने की दिशा में सहकारिता क्षेत्र अब नई और व्यापक भूमिका निभाने जा रहा है। किसानों की राष्ट्रीय सहकारी समिति नेफेड ने आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा जारी रखने के लिए 'किसान कल्याण योजना' के तहत स्कॉलरिशिप देने की शुरुआत की है। यह योजना किसान परिवारों के उन विद्यार्थियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है, जिनकी प्रतिभा और मेहनत के बावजूद सीमित पारिवारिक आय उच्च शिक्षा की राह में बाधा बन जाती है।

सहकार से समृद्धि के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) ने किसान परिवारों के योग्य विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी व्यावसायिक, तकनीकी या उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। इसके तहत पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी वित्तीय दबाव के पूरी कर सकें। नेफेड ने इस योजना पर अपने मुनाफे का एक प्रतिशत हिस्सा खर्च करने का ऐलान किया है।

भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा की मजबूत नींव किसान हैं। खेतों में कठिन परिश्रम करने वाले लाखों परिवार देश के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, लेकिन उनकी आय का बड़ा हिस्सा खेती, खाद, बीज, सिंचाई, पशुपालन और घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च हो जाता है। ऐसे में बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाना कई परिवारों के लिए कठिन हो जाता है। फीस, पुस्तकें, छात्रावास, परिवहन और तकनीकी प्रशिक्षण से जुड़ा खर्च कई बार विद्यार्थियों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है।

किसान कल्याण योजना पर मुनाफे का एक प्रतिशत करेगा खर्च

किसान कल्याण योजना इसी चुनौती का समाधान है। स्कॉलरशिप से परिवारों पर शिक्षा का आर्थिक बोझ कम होता है और विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। योजना का लाभ मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों के युवा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, प्रबंधक, शिक्षक और कुशल तकनीकी पेशेवर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इससे केवल एक विद्यार्थी का भविष्य नहीं बदलता, बल्कि पूरे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना पैदा होती है।

यह पहल ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उच्च शिक्षा प्राप्त युवा आधुनिक कृषि तकनीकों, डिजिटल सेवाओं, कृषि विपणन, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित कर सकते हैं। शिक्षित युवा अपने परिवारों को बेहतर निर्णय लेने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने में भी सहायता कर सकते हैं।

नेफेड की योजना यह भी स्पष्ट करती है कि सहकारिता अब केवल कृषि उपज की खरीद, भंडारण, विपणन, ऋण और खाद-बीज वितरण तक सीमित नहीं है। सहकारी संस्थाएं शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और मानव संसाधन निर्माण में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। किसान परिवारों के बच्चों में किया गया यह निवेश लंबे समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक असमानता कम करने में सहायक हो सकता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देकर नेफेड न केवल उनके सपनों को नई उड़ान दे रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए शिक्षित, कुशल और सक्षम युवा पीढ़ी भी तैयार कर रहा है।■

सहकारिता आधारित विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एनसीडीसी की भूमिका होगी महत्वपूर्ण

एनसीडीसी छू रहा नई ऊंचाइयां

वित्त वर्ष 2025-26 में 1.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का किया कारोबार, 34 प्रतिशत की दर्ज की वृद्धि

कृषि विपणन और खेती के इनपुट के लिए 1,02,436.04 करोड़ रुपये की सर्वाधिक राशि बांटी गई

एनसीडीसी ने इस दौरान नेट एनपीए शून्य बनाए रखा और 1,275 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ भी कमाया

युवा सहकार टीम

भारत में सहकारिता आंदोलन आज केवल किसानों को सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला एक मजबूत विकास मॉडल बन चुका है। इस बदलाव के केंद्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) है जिसने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने इतिहास का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज करते हुए सहकारिता क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी है। रिकॉर्ड ऋण वितरण, मजबूत वित्तीय अनुशासन और नई योजनाओं के माध्यम से एनसीडीसी ने यह साबित किया है कि सहकारिता देश के समावेशी आर्थिक विकास की सबसे प्रभावी ताकत बन सकती है।

वित्त वर्ष 2025-26 में एनसीडीसी ने 1,55,370.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की, जबकि 1,27,596.28 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया। यह अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक वितरण है और इसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 95,182.88 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 2014-15 में जहां एनसीडीसी का ऋण वितरण केवल 5,735 करोड़ रुपये था, वहीं एक दशक में यह बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। यह वृद्धि सहकारिता क्षेत्र में बढ़ते विश्वास और सरकार की

प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत है।

एनसीडीसी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने रिकॉर्ड कारोबार के बावजूद शून्य नेट एनपीए बनाए रखा। साथ ही निगम ने 1,275 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो उसकी स्थापना के बाद का सर्वाधिक लाभ है। यह उपलब्धि बताती है कि सामाजिक उद्देश्य और वित्तीय अनुशासन एक साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं।

वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि विपणन और कृषि इनपुट क्षेत्र को मिला जहां 1,02,436.04 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इसके अलावा औद्योगिक क्रेडिट और सेवा सहकारी समितियों को 15,370.22 करोड़ रुपये दिये गये। जबकि कृषि-प्रसंस्करण को 8,232.53 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, जनजातीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हथकरघा, कॉयर, जूट, रेशम उत्पादन और महिला सहकारी समितियों को कवर करने वाले कमजोर वर्ग के कार्यक्रमों को 1,128.55 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इससे स्पष्ट है कि एनसीडीसी का दायरा केवल कृषि ऋण तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण ग्रामीण आर्थिक तंत्र को मजबूत करने तक विस्तारित हो चुका है।

एनसीडीसी का यह क्षेत्रीय विस्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सहकारी विकास केवल ऋण वितरण तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का वित्तीय कारोबारी दायरा समूचे सहकारी आर्थिक तंत्र में फैला हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एनसीडीसी ने कृषि विपणन के साथ कृषि इनपुट में शामिल कृषि-प्रसंस्करण, चीनी, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, अन्न भंडारण और कोल्ड चेन, क्रेडिट और सेवा सहकारी समितियां, एफपीओ, निर्यात संवर्धन और कमजोर वर्ग की सहकारी समितियों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराया है। इसके लिए फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे, प्रसंस्करण क्षमता, कार्यशील पूंजी, बाजार लिंकेज, भंडारण, प्रौद्योगिकी, पेशेवर प्रबंधन और जोखिम-अनुकूल फंडिंग की आवश्यकता होती है। एनसीडीसी की सहायता ने सहकारी समितियों को अपने बिजनेस मॉडल को मजबूत करने, सदस्य सेवाओं में सुधार करने और आधुनिक बाजारों व वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद की है।

पूंजी की कमी से जूझते लोगों के लिए संजीवनी

सहकारिता क्षेत्र की लघु से लेकर वृहद संस्थाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देश के उन 60 करोड़ लोगों पर सरकार की नजर है जो पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं। सहकारिता मंत्री

एनसीडीसी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने रिकॉर्ड कारोबार के बावजूद शून्य नेट एनपीए बनाए रखा। साथ ही निगम ने 1,275 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो उसकी स्थापना के बाद का सर्वाधिक लाभ है। यह उपलब्धि बताती है कि सामाजिक उद्देश्य और वित्तीय अनुशासन एक साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं।

एनसीडीसी का यह क्षेत्रीय विस्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सहकारी विकास केवल ऋण वितरण तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का वित्तीय कारोबारी दायरा समूचे सहकारी आर्थिक तंत्र में फैला हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एनसीडीसी ने कृषि विपणन के साथ कृषि इनपुट में शामिल कृषि-प्रसंस्करण, चीनी, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, अन्न भंडारण और कोल्ड चेन, क्रेडिट और सेवा सहकारी समितियां, एफपीओ, निर्यात संवर्धन और कमजोर वर्ग की सहकारी समितियों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराया है।

के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) उन्हें वित्तीय मदद मुहैया कराने में अहम भूमिका निभा रहा है। अमित शाह का कहना है कि केंद्र सरकार सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर देश के गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2021 में गठित सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को मजबूत करने पर सरकार का विशेष ध्यान है।

कृषि से लेकर युवा उद्यम तक को लाभ

सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं ने भी इस परिवर्तन को नई गति दी है। युवा सहकार, आयुष्मान सहकार, डेयरी सहकार, डिजिटल सहकार, स्वयं शक्ति सहकार और नंदिनी सहकार जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, डेयरी उद्यमियों, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल नवाचारों को वित्तीय सहायता मिल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। जैसे-जैसे सहकारी समितियों का देशव्यापी विस्तार हो रहा है उसी तरह सुलभ वित्त प्रदान करने, क्षमता निर्माण और रणनीतिक क्षेत्रीय हस्तक्षेप में एनसीडीसी की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। निरंतर प्रयासों के माध्यम से एनसीडीसी न केवल सहकारी संस्थाओं को सशक्त बना रहा है, बल्कि आत्मनिर्भरता और सतत ग्रामीण समृद्धि की दिशा में भारत की यात्रा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की रणनीति के केंद्र में वह सहकारी समितियां हैं जो अब तक हाशिए पर रही हैं। मत्स्य पालन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पहाड़ी समितियां, हथकरघा, डेयरी, कुक्कुट पालन और महिला श्रमिक समितियां की सुध लेने वाला कोई नहीं था। सरकार का यह कदम सहकारिता क्षेत्र में समावेशी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगा। इसी के बूते देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण होगी। एनसीडीसी ने पिछले चार वित्तीय वर्षों में कुल 1,621 ऋण स्वीकृत और वितरित किए हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 2,31,053.79 करोड़ रुपये है। इससे ग्राम स्तर की प्राथमिक सहकारी समितियों की दशा में सुधार हुआ है।

पैक्स से अपेक्स तक हो रहे लाभान्वित

देश की आठ लाख से ज्यादा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पैक्स) प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को एनसीडीसी से ही रियायती दरों पर ऋण प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को पूरा करने में एनसीडीसी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है। एनसीडीसी देश भर की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय मदद पहुंचाती है। इसके माध्यम से सहकारिता की निचली इकाई पैक्स से लेकर शीर्ष इकाई अपेक्स तक को भरपूर वित्तीय

मदद मुहैया कराई जा रही है। एनसीडीसी के इस कदम से राज्यों और सहकारी संस्थाओं को कृषि, सहकारिता और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में निवेश और विस्तार के लिए मजबूती मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास से देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती मिल रही है। रोजगार के साधन बढ़े हैं। सुनिश्चित खाद्यान्न आपूर्ति से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिली है। किसानों की उपज की खरीद, भंडारण और वितरण क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को सरकार की ओर से दी गई सहूलियतों के चलते उनके कारोबार में वृद्धि हुई है।

फसलों की सरकारी खरीद को समर्थन

किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सहकारिता मंत्रालय की पहल उल्लेखनीय है। कृषि उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होने वाली खरीद को सहकारिता मंत्रालय समर्थन करता है। इसके तहत राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के साथ राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आगे बढ़कर उपज की खरीद करते हैं। इसके लिए एनसीडीसी राज्यों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रहा है। केंद्र सरकार रबी और खरीफ सीजन की 24 फसलों की एमएसपी और गन्ने की उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के साथ तीन अन्य कमर्शियल फसलों की एमएसपी की घोषणा करती है। विभिन्न राज्यों की कृषि मंडियों में उपज की कीमतें नीचे होने की दशा में एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू की जाती है। कोऑपरेटिव एजेंसियों के लिए कार्यशील पूंजी का बंदोबस्त एनसीडीसी करता है। एनसीडीसी ने किसानों की चुनौतियों के समाधान के लिए एमएसपी पर होने वाली उनकी उपज की खरीद व अन्य इनपुट के बाबत विभिन्न राज्यों में सहकारी मार्केटिंग सोसाइटियों को वर्ष 1,02,436.04 करोड़ रुपये की सर्वाधिक राशि बांटी गई

डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास में बढ़ी भूमिका

सहकारिता मंत्रालय के फोकस एरिया में देश के लघु व सीमांत किसानों के साथ भूमिहीन किसानों की दशा को सुधारने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियां हैं। डेयरी क्षेत्र की सहकारी समितियों को मजबूत कर ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एनसीडीसी डेयरी सहकार नाम से एक योजना चलाती है। इस योजना का मकसद सहकारी समितियों के आधारभूत ढांचे का निर्माण, आधुनिकीकरण और विस्तार में मदद करना है। इसके लिए सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण, ऋण गारंटी और वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

एनसीडीसी मत्स्य सहकारी समितियों को उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन आदि से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता प्रदान करता है। इन गतिविधियों में मछली पकड़ने वाली नावों, जालों और इंजनों जैसे परिचालन इनपुट की खरीद करने के अलावा विपणन, परिवहन वाहनों, बर्फ संयंत्रों, शीतगृहों, खुदरा दुकानों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का निर्माण करना शामिल है। साथ ही अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जल संवर्धन, बीज फार्म, हैचरी आदि का विकास, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, एकीकृत मत्स्य पालन परियोजनाएं (समुद्री, अंतर्देशीय और खारे पानी) और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज की खरीद के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है। मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें 40-60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के तहत सहकारी समितियों को तीन प्रतिशत तक ब्याज सहायता और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएमएमकेएसएसवाई) के तहत 35 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन सब्सिडी दी जाती है।

कोऑपरेटिव बैंकों को भी वित्तीय मदद

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में एनसीडीसी और नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने मिलकर कोऑपरेटिव बैंकों को 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की। एनसीडीसी की ओर से इस अवधि में आंध्र प्रदेश (3,730 करोड़ रुपये) और तेलंगाना (2,000 करोड़ रुपये) के कोऑपरेटिव बैंकों को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद दी गई, जबकि मध्य प्रदेश (291 करोड़ रुपये) और राजस्थान (77 करोड़

कृषि उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होने वाली खरीद को सहकारिता मंत्रालय समर्थन करता है। इसके तहत राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के साथ राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आगे बढ़कर उपज की खरीद करते हैं। इसके लिए एनसीडीसी राज्यों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रहा है।

> सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं ने भी इस परिवर्तन को नई गति दी है। युवा सहकार, आयुष्मान सहकार, डेयरी सहकार, डिजिटल सहकार, स्वयं शक्ति सहकार और नंदिनी सहकार जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, डेयरी उद्यमियों, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल नवाचारों को वित्तीय सहायता मिल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

रुपये) को भी वित्तीय सहयोग मिला। इसी तरह, नाबार्ड के वितरण में मध्य प्रदेश को सबसे अधिक 4,430 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके बाद ओडिशा (4,113 करोड़ रुपये) और कर्नाटक (3,655.52 करोड़ रुपये) को लाभ मिला। नाबार्ड के अन्य प्रमुख आवंटनों में तमिलनाडु (2,946.49 करोड़ रुपये), राजस्थान (2,760.75 करोड़ रुपये), आंध्र प्रदेश (2,716.55 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (2,696.26 करोड़ रुपये) और गुजरात (1,691.31 करोड़ रुपये) शामिल हैं। वित्तीय प्रवाह और डिजिटल एकीकरण के साथ सहकारी बैंकिंग क्षेत्र आने वाले वर्षों में ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगा।

एनसीडीसी का बढ़ता दायरा

देश के 29 करोड़ किसान सहकारिता से जुड़े हैं। 1963 में अपनी स्थापना के बाद से एनसीडीसी कृषि और बागवानी सहकारी समितियों सहित अन्य सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। एनसीडीसी की क्षमता को पहचानते हुए इसे सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना के तहत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए सहयोग के साथ ही एफपीओ के रूप में नई सहकारी समितियों का पंजीकरण और उन्हें समर्थन प्रदान करती है। अब तक 1863 एफपीओ का गठन हो चुका है। इसी तरह निर्यात, जैविक और बीज उत्पादन पर गठित तीन राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर भी एनसीडीसी का ध्यान है।

खाद्यान्न प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा

केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना का शुभारंभ किया है, जिसपर एक लाख करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। गोदामों का निर्माण करने, खाद्यान का भंडारण, विपणन और प्रसंस्करण का दायित्व प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) समेत अन्य सहकारी संस्थाओं को सौंपा गया है। इससे कुल सात करोड़ टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालयी समिति की देखरेख में यह

योजना काम कर रही है, जिसका बड़ा दायित्व एनसीडीसी को सौंपा गया है। एनसीडीसी ही इस योजना को वित्तीय मदद मुहैया करा रहा है। इसी तरह खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र में काम कर रही सहकारी क्षेत्र की चावल, दाल, गेहूं व मक्का आटा मिलों और पशुचारा इकाइयों को एनसीडीसी से वित्तीय आवंटन के साथ अनुदान प्राप्त हो रहा है। बागवानी फसलों में फल-फूल और मसालों के साथ अन्य कमर्शियल उपज की प्रसंस्करण इकाइयों की पूंजी की जरूरतें भी यहीं से पूरी की जाती हैं। इन फसलों की उपज की निर्यात में बड़ी भागीदारी होने की वजह से सहकारिता मंत्रालय का जोर इस पर ज्यादा है।

सहकारी चीनी उद्योग को मदद

सहकारी चीनी उद्योग और उससे जुड़े उद्योगों और कोजेनरेशन इकाइयों, कताई मिलों, कपास जिनिंग, प्रेसिंग, पावरलूम, तेल मिलों, चावल व दाल मिलों, काफी, चाय, रबड़, फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों समेत कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, आधुनिकीकरण विस्तार व विविधीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1950 में जहां सहकारी क्षेत्र में केवल दो चीनी मिलें थी वह आज बढ़कर 312 तक पहुंच गई हैं। देश के कुल चीनी उत्पादन में सहकारी चीनी मिलों की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना, पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण और पेराई क्षमता के विस्तार के लिए सहायता दी जाती है। चीनी निर्यात में भी सहकारी चीनी मिलों की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। फिलहाल सहकारिता मंत्रालय का पूरा जोर चीनी उत्पादन के साथ एथनॉल उत्पादन पर है। सहकारी चीनी मिलों को एथेनॉल संयंत्र, सह उत्पादन संयंत्र की स्थापना और कार्यशील पूंजी के लिए एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 48 मिलों को 9,893.12 करोड़ रुपये के 87 लोन स्वीकृत किए हैं। 2024-25 में इन्हें 7,975.54 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

सर्विस कोऑपरेटिव पर फोकस

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सेवा सहकारिता (सर्विस कोऑपरेटिव) क्षेत्र पर खूब जोर है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से ग्रामीण युवाओं को नए उद्यम शुरू करने का भी मौका देता है। जल संरक्षण कार्य और सेवाएं, सिंचाई संसाधनों में सूक्ष्म सिंचाई के साथ पशुधन विकास और स्वास्थ्य सेवा और बीमारियों को रोकथाम जैसे कार्यों को सहकारिता क्षेत्र में खास तरजीह दी जाती है। इस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाली सहकारिताओं को विशेष तवज्जो की गई है। सहकारिता के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्राथमिकता वाले क्षेत्र ग्रामीण स्वच्छता, जल निकासी और ग्रामीण सीवेज प्रणाली को सहायता प्रदान की जाती है।■

सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना, पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण और पेराई क्षमता के विस्तार के लिए सहायता दी जाती है। चीनी निर्यात में भी सहकारी चीनी मिलों की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। फिलहाल सहकारिता मंत्रालय का पूरा जोर चीनी उत्पादन के साथ एथनॉल उत्पादन पर है।

सहकार भारती का बजा डंका

20 डायरेक्टर्स में से 19 सहकार भारती और भाजपा गठबंधन के विजयी रहे

सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से ग्रुप-2 निर्वाचन क्षेत्र के नतीजों की औपचारिक घोषणा बाद में होगी

युवा सहकार टीम

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के गवर्निंग काउंसिल के लिए हुए चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। सहकारी चुनाव प्राधिकरण यानी सीईए ने ग्रुप-2 निर्वाचन क्षेत्र के नतीजों को छोड़कर बाकी निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए हैं। हालांकि, ग्रुप-2 निर्वाचन क्षेत्र जिसमें राष्ट्रीय सहकारी समितियां शामिल हैं, के अनौपचारिक नतीजे आ गए हैं और पता चल गया है कि किसकी जीत और किसकी हार हुई है। चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए कोर्ट के आदेश के बाद ही इस निर्वाचन क्षेत्र के नतीजों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इसकी वजह से एनसीयूआई चेयरमैन, वॉइस चेयरमैन और बोर्ड के अन्य पदाधिकारियों के चुनाव में अभी समय लगेगा। इनका चुनाव बोर्ड के डायरेक्टर्स ही करते हैं।

एनसीयूआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में सहकार भारती का डंका बजा है क्योंकि देश की सहकारी समितियों के शीर्ष संगठन के बोर्ड में सहकार भारती से संबद्ध रखने वाले कई सदस्यों की जीत हुई है। ये सहकार भारती से जुड़े विभिन्न सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के तौर पर इस चुनाव में उतरे थे और विजयी रहे। इस चुनाव में सहकार भारती और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संयुक्त गठबंधन ने शानदार सफलता हासिल की। गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों ने 20 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें से 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। मतदान 18 जुलाई को हुआ और 19 जुलाई को मतगणना के बाद अनौपचारिक परिणाम घोषित किए गए। बाद में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाले सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए) ने एनसीयूआई की शासी परिषद के 15 सदस्यों के चुनाव नतीजों को मंजूरी दे दी है, जबकि समूह-2 (राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां/संघ) निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम को

सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही के कारण लंबित रखा गया है।

एनसीयूआई चुनाव में विजयी रहे प्रमुख लोगों में सहकार भारती के संरक्षक दीनानाथ ठाकुर, इफको के चेयरमैन दिलीप संघाणी, एनडीडीबी के चेयरमैन मिनेश शाह, कृभको के डायरेक्टर बिपिन पटेल, नेफेड के डायरेक्टर मोहनभाई कुंडारिया, एनसीसीएफ के चेयरमैन विशाल सिंह शामिल हैं। इनके अलावा विनय कुमार शाही, प्रवीण दरेकर, जी.टी. देवेगौड़ा, सुश्री जीना पोत्संगबम, जीएच अमीन, एनसीडीसी के डायरेक्टर धनंजय सिंह, एच.के. पाटील, मुदित वर्मा, अण्णासाहेब जोल्हे, नकुल कड़ू सहित अन्य उम्मीदवार शामिल हैं।

इन विजयी उम्मीदवारों में एचके पाटिल को छोड़कर बाकी सभी सहकार भारती या फिर भाजपा से जुड़े हुए हैं। सहकार भारती की यह सफलता केवल चुनावी विजय नहीं है, बल्कि उन लाखों सहकारी कार्यकताओं और प्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों का सम्मान है जिन्होंने वर्षों से सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय पाचपोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी, संरक्षक दीनानाथ ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों और समस्त सहकार बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि नए नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारतीय सहकारिता आंदोलन को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) के अभिषेक कुमार ने भी एनसीयूआई शासी परिषद चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दीं।

एनसीयूआई की गवर्निंग काउंसिल के लिए 20 डायरेक्टर्स चुने गए हैं। इनमें से 10 का चुनाव निर्विरोध हुआ था जबकि बाकी 10 डायरेक्टर्स के लिए मतदान कराया गया। मतदान के दो नतीजे बड़े दिलचस्प रहे हैं। एक है राज्य स्तरीय अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों और क्रेडिट सोसायटी फेडरेशन निर्वाचन क्षेत्र का और दूसरा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी निर्वाचन क्षेत्र का। राज्य स्तरीय अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों और क्रेडिट सोसायटी फेडरेशन निर्वाचन क्षेत्र में कर्नाटक के कांग्रेसी नेता एच.के. पाटिल और सहकार भारती के सुनील गुप्ता के बीच मुकाबला 4-4 वोट की बराबरी पर रहा। इसके बाद नियमों के तहत लॉटरी निकाली गई, जिसमें एच.के. पाटिल की किस्मत चमकी और वे जीत गए।

इसी तरह मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए सहकार भारती समर्थित नकुल काडू ने संजय भेंडे को 14-12 के अंतर से हराकर सभी को चौंका दिया।

बाकी निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे उम्मीद के अनुसार ही रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव सोसायटी के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुने गए डायरेक्टर्स में एनसीसीएफ चेयरमैन विशाल सिंह, इफको चेयरमैन दिलीप संघाणी, एनडीडीबी चेयरमैन मीनेश शाह सहित नेफेड के डायरेक्टर मोहनभाई कुंडारिया और कृभको के डायरेक्टर बिपिन भाई पटेल शामिल हैं। जबकि दलीप सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा है। एनसीयूआई के अन्य प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुए चुनाव में स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन निर्वाचन क्षेत्र से बिहार के विनय कुमार शाही और मणिपुर की जीना पोत्सांगबाम ने आसान जीत दर्ज की। पश्चिमी और दक्षिणी भारत के राज्य स्तरीय सहकारी महासंघ निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व भाजपा सांसद अन्नासाहेब जोले ने एकतरफा जीत हासिल की।

इस चुनाव में सहकार भारती को मिला व्यापक समर्थन संगठन की वर्षों की सक्रियता, मजबूत संगठनात्मक आधार तथा सहकारी मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण माना जा रहा है।■

इन विजयी उम्मीदवारों में एचके पाटिल को छोड़कर बाकी सभी सहकार भारती या फिर भाजपा से जुड़े हुए हैं। सहकार भारती की यह सफलता केवल चुनावी विजय नहीं है, बल्कि उन लाखों सहकारी कार्यकताओं और प्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों का सम्मान है जिन्होंने वर्षों से सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय पाचपोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी, संरक्षक दीनानाथ ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों और समस्त सहकार बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

अमूल बंगाल में लगाएगी सबसे बड़ा दही प्लांट

10 लाख किलो रोजाना दही उत्पादन की होगी क्षमता और 30 लाख लीटर दूध की होगी प्रोसेसिंग

सहकारिता मॉडल से मजबूत होगा बंगाल का डेयरी क्षेत्र, श्वेत क्रांति 2.0 को मिलेगी गति

अमूल के मेगा डेयरी प्लांट से 1.20 लाख पशुपालकों को मिलेगा लाभ

700 करोड़ रुपये की इस परियोजना से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

युवा सहकार टीम

दुनिया की नंबर वन और देश की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव अमूल पश्चिम बंगाल में अपना सबसे बड़ा दही प्लांट लगाने जा रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा फूड पार्क में लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली यह परियोजना न केवल राज्य के डेयरी क्षेत्र को नई पहचान देगी, बल्कि लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा देश में 'श्वेत क्रांति 2.0' के लक्ष्य को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने इस प्लांट का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि यह परियोजना केवल एक औद्योगिक निवेश नहीं, बल्कि किसानों और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि से जुड़ा एक बड़ा अभियान है।

30 लाख लीटर रोजाना दूध की होगी प्रोसेसिंग

अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के पहले चरण में प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा। परियोजना पूरी तरह शुरू होने के बाद इसकी क्षमता बढ़कर 30 लाख लीटर दूध प्रतिदिन हो जाएगी, जिससे यह पूर्वी भारत के सबसे बड़े डेयरी प्रसंस्करण केंद्रों में शामिल हो जाएगी। इससे करीब 1.20 लाख

छोटे दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका दही उत्पादन प्लांट होगा। यहां प्रतिदिन 1,000 टन यानी 10 लाख किलोग्राम दही एवं अन्य कल्चर्ड डेयरी उत्पादों का उत्पादन किया जा सकेगा। इसी क्षमता के कारण इसे दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट माना जा रहा है। इसके अलावा यहां प्रतिदिन 10 लाख लीटर पैकेज्ड दूध, 2 लाख लीटर यूएचटी दूध, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 मीट्रिक टन पनीर, 10 मीट्रिक टन घी, 10 मीट्रिक टन मिठाइयों तथा लगभग 2.5 लाख पैक फ्लेवर्ड मिल्क का भी उत्पादन किया जाएगा। इससे पश्चिम बंगाल आधुनिक डेयरी उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र बन सकेगा।

किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार और उचित मूल्य

इस परियोजना से राज्य के दुग्ध उत्पादकों को अपने दूध के लिए एक स्थायी, पारदर्शी और बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। अभी कई छोटे पशुपालक स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता। आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण, कोल्ड चेन और संगठित खरीद प्रणाली विकसित होने से किसानों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए हावड़ा फूड पार्क में 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। इससे केवल डेयरी उद्योग ही नहीं, बल्कि पैकेजिंग, परिवहन, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कई सहायक क्षेत्रों में भी निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।

अमूल आज दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्थाओं में शामिल है। इससे 36 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में 18,600 से अधिक ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां अमूल नेटवर्क का हिस्सा हैं और देश के लगभग सभी राज्यों तक इसके उत्पाद पहुंच रहे हैं। सहकारिता मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई राशि का बड़ा हिस्सा सीधे उत्पादक तक पहुंचता है। जब कोई उपभोक्ता अमूल के उत्पादों पर 100 रुपये खर्च करता है तो लगभग 87 रुपये सीधे किसानों और पशुपालकों के बैंक खातों में पहुंचते हैं। यही मॉडल किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में जल संसाधनों, उपजाऊ भूमि और पशुपालन की पर्याप्त संभावनाओं को देखते हुए यह परियोजना राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। आधुनिक डेयरी अवसंरचना विकसित होने से दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन का पूरा तंत्र

पशुओं की नस्ल सुधार पर रहेगा विशेष जोर

सरकार ने परियोजना के साथ-साथ डेयरी उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपायों पर भी जोर देने की बात कही है। इसके तहत पश्चिम बंगाल में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, जिससे अधिक दूध देने वाली दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाई जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 15 वर्षों में राज्य के पशुपालकों के पास ऐसी उन्नत नस्लों के पशु उपलब्ध हों जो वर्तमान नस्लों की तुलना में कम से कम 25 प्रतिशत अधिक दूध दें। इससे दूध उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित 70 से अधिक किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अगले छह महीनों के भीतर पश्चिम बंगाल के किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

इस परियोजना से राज्य के दुग्ध उत्पादकों को अपने दूध के लिए एक स्थायी, पारदर्शी और बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। अभी कई छोटे पशुपालक स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता। आधुनिक डेयरी प्रसंस्करण, कोल्ड चेन और संगठित खरीद प्रणाली विकसित होने से किसानों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है।

मजबूत होगा। इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

अमूल बंगाल डेयरी परियोजना केवल एक डेयरी संयंत्र नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, सहकारिता मॉडल को मजबूत करने, आधुनिक तकनीक को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने और भारत में श्वेत क्रांति 2.0' को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र के रूप में यह परियोजना न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के डेयरी क्षेत्र के लिए एक नई पहचान स्थापित कर सकती है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की अपनी सहकारी डेयरी संस्थाओं को मजबूत करने की बजाय अमूल जैसी गुजरात आधारित बड़ी सहकारी संस्था को इतनी व्यापक भूमिका क्यों दी जा रही है।

हालांकि, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की अपनी सहकारी डेयरी संस्थाओं को मजबूत करने की बजाय अमूल जैसी गुजरात आधारित बड़ी सहकारी संस्था को इतनी व्यापक भूमिका क्यों दी जा रही है। क्या यह परियोजना स्थानीय सहकारी नेटवर्क को सशक्त करेगी या फिर राज्य के मौजूदा डेयरी संगठनों और छोटे कारोबारियों के सामने एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी खड़ा कर देगी?

राज्य में वर्षों से बंगाल मिल्क फेडरेशन और अन्य स्थानीय दुग्ध सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। यदि यही निवेश राज्य की अपनी सहकारी व्यवस्था के विस्तार, आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि पर किया जाता तो स्थानीय संस्थाएं अधिक मजबूत बन सकती थीं और उनका बाजार भी बढ़ सकता था। अमूल जैसे राष्ट्रीय ब्रांड की मजबूत विपणन क्षमता के सामने स्थानीय डेयरी ब्रांडों के लिए प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं होगा। इससे भविष्य में राज्य की छोटी डेयरी सहकारी समितियों और स्थानीय दुग्ध संघों की बाजार हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। यदि सरकारी खरीद और निवेश का झुकाव बड़े राष्ट्रीय ब्रांड की ओर बढ़ता है, तो स्थानीय संस्थाएं धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती हैं।

एक अन्य सवाल किसानों की निर्भरता को लेकर भी उठ रहा है। यदि दूध संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन का बड़ा हिस्सा एक ही संस्था के हाथों में केंद्रित हो जाता है, तो भविष्य में किसानों के पास विकल्प सीमित हो सकते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सहकारी संस्थाओं को समान अवसर मिलना आवश्यक है।■

महिला समूहों को डेयरी से जोड़ेगी हरियाणा सरकार

युवा सहकार टीम

- **हरियाणा में खुलेंगे 700 नए वीटा बूथ, रोजगार और दुग्ध कारोबार को मिलेगी रफ्तार**
- **रेलवे स्टेशन से अस्पताल तक खुलेंगे वीटा बूथ, बढ़ेंगे स्वरोजगार के अवसर**

हरियाणा सरकार सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण रोजगार, महिला उद्यमिता और दुग्ध व्यवसाय को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश भर में 700 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि वीटा उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के साथ युवाओं और महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएं। वीटा हरियाणा का कोऑपरेटिव दूध ब्रांड है। अब तक 143 महिला स्वयं सहायता समूह दूध की बिक्री के लिए सहमति जता चुके हैं। इन समूहों को दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, दूध की गुणवत्ता, संग्रहण और विपणन से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण देने की भी योजना है। इससे ग्रामीण महिलाओं को अपने गांव में ही आजीविका का स्थायी साधन मिलेगा और परिवार की आय बढ़ाने में उनकी भूमिका मजबूत होगी।

वीटा बूथों के विस्तार की योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 674 बूथ शुरू किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 318 बूथ जल्द शुरू किए जाएंगे, जबकि 240 अन्य बूथों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। अब तक वीटा बूथ मुख्य रूप से बस अड्डों और प्रमुख बाजारों में संचालित किए जा रहे थे। सरकार ने इनके विस्तार के लिए रेलवे स्टेशनों, पर्यटन स्थलों, अस्पतालों, आवासीय सोसायटियों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को भी चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।

इन बूथों के माध्यम से दूध, दही, घी, लस्सी, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पाद उपभोक्ताओं को आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही बूथ संचालन से युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को नियमित आय का साधन मिलेगा। वीटा के बिक्री नेटवर्क का विस्तार होने से सहकारी दुग्ध समितियों से जुड़े पशुपालकों के दूध की मांग भी बढ़ेगी। सरकार का विशेष जोर सहकारी समितियों से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। साझा डेयरी योजना के अंतर्गत महिला समूहों को पंचायती भूमि पर पशु शेड उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। पशु खरीदने के लिए उन्हें ऋण सुविधा भी दी जाएगी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स के माध्यम से महिला समूहों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

दूध उत्पादकों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि करेगी। सर्दियों के मौसम में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को तीन रुपये से बढ़ाकर पांच रुपये प्रति लीटर किया जाएगा। गर्मियों में यह राशि पांच रुपये से बढ़ाकर सात रुपये प्रति लीटर करने की तैयारी है। इसके अतिरिक्त दुग्ध विपणन सहायता में भी तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की जाएगी। प्रोत्साहन राशि बढ़ने से पशुपालकों को उत्पादन लागत की भरपाई करने में मदद मिलेगी। गर्मियों में पशुओं के चारे, देखभाल और दूध उत्पादन पर खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में अतिरिक्त सहायता से पशुपालकों को सहकारी दुग्ध समितियों को दूध बेचने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे निजी खरीदारों पर उनकी निर्भरता भी कम होगी और भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था मजबूत होगी।

हरियाणा की सहकारी समितियां वर्तमान में प्रतिदिन लगभग पांच लाख लीटर दूध खरीद रही हैं। दूध की बढ़ती खरीद और प्रसंस्करण की जरूरत को देखते हुए बावल और अंबाला में 1.50 लाख लीटर क्षमता वाले दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन संयंत्रों से दूध के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विभिन्न दुग्ध उत्पादों के निर्माण की क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में पांच हजार से दस हजार लीटर क्षमता वाले 21 मिल्क चिलिंग सेंटर स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों से संग्रहित दूध को तुरंत ठंडा किया जा सकेगा, जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी और खराब होने की आशंका कम होगी। दूरदराज के क्षेत्रों के पशुपालकों को भी अपनी उपज निकटतम केंद्र पर बेचने की सुविधा मिलेगी।

दुग्ध संयंत्रों, चिलिंग सेंटरों और वीटा बूथों का यह नेटवर्क उत्पादन से लेकर विपणन तक पूरी श्रृंखला को मजबूत करेगा। इससे पशुपालकों को नियमित बाजार, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का लक्ष्य सहकारिता को केवल दूध की खरीद-बिक्री तक सीमित न रखकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाना है। महिला समूहों की भागीदारी, पशुपालकों के लिए अधिक प्रोत्साहन और वीटा के विस्तारित बिक्री नेटवर्क से हरियाणा में दुग्ध कारोबार को नई गति मिलने की उम्मीद है। यह पहल सहकारिता के माध्यम से रोजगार, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण समृद्धि को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रभावी मॉडल बन सकती है।■

हुनर से आत्मनिर्भरता तक

युवाओं के भविष्य को संवारती एनवाईसीएस की कौशल विकास पहल

युवा सहकार टीम

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवाओं और महिलाओं को रोजगार योग्य बनाने की दिशा में समर्थ युवा फाउंडेशन और नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है।

परियोजना के अंतर्गत प्रतिभागियों को तीन महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें जूनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन और पाइप फिटर जैसे रोजगारपरक ट्रेड शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव, आत्मविश्वास, जीवन कौशल और उद्यमिता की समझ भी प्रदान की जा रही है।

कार्यक्रम के तहत जूनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट ट्रेड में पेशेवर प्रशिक्षण देकर प्रतिभागियों को पर्सनल केयर, ग्रूमिंग और सैलून से जुड़ी बुनियादी सेवाओं में करियर बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों में तकनीकी दक्षता एवं उद्यमशीलता का विकास किया जा रहा है, ताकि वे स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। इसके अतिरिक्त, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सुरक्षा एवं निगरानी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं, पाइप फिटर (ऑयल एंड गैस/सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) प्रशिक्षण उन्हें शहरी अवसंरचना एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े तकनीकी कार्यों के लिए सक्षम बनाता है। ये सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं।

परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रतिभागियों के कौशल विकास और व्यावहारिक अनुभव को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण सत्र, कौशल मूल्यांकन, औद्योगिक भ्रमण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम

प्रतिभागियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने तथा सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक जानकारी एवं कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास कार्यक्रम और जीवन कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस सत्र में व्यवसाय की योजना तैयार करने, वित्तीय प्रबंधन, बाजार की समझ, ग्राहकों तक पहुंचने के तरीके, सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं की जानकारी सरल भाषा में दी गई। प्रमाणित मास्टर ट्रेनर ने अपने अनुभव साझा करते हुए प्रतिभागियों को छोटे स्तर से व्यवसाय शुरू करने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर उद्यमी बनाकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना था।

औद्योगिक भ्रमण एवं मूल्यांकन

प्रशिक्षण को व्यावहारिक अनुभव से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतिभागियों को एक प्रतिष्ठित ब्यूटी पार्लर का औद्योगिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान उन्हें आधुनिक ब्यूटी तकनीकों, उपकरणों के उपयोग, ग्राहक सेवा, स्वच्छता मानकों और ब्यूटी इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली को निकट से समझने का अवसर मिला। इससे उनके ज्ञान, कार्यकुशलता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। भ्रमण के बाद जूनियर ब्यूटी थेरेपिस्ट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का कौशल मूल्यांकन आयोजित किया गया। इसमें त्वचा की दैनिक देखभाल, सुरक्षित एवं सरल मेकअप तकनीक, सेल्फ मेकअप डेमो, ग्राहकों से प्रभावी संवाद तथा स्वच्छता एवं सुरक्षा मानकों के पालन जैसे विषयों पर उनकी समझ और व्यावहारिक कौशल का आकलन किया गया। प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रतिभागियों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान निर्धारित मानकों के अनुसार निष्पक्ष रूप से जांचा गया। मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूर्ण

करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। यह प्रमाणपत्र उनके कौशल को आधिकारिक मान्यता देने के साथ रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होगा।

इसी तरह, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन ट्रेड के अंतर्गत प्रतिभागियों का कौशल मूल्यांकन आयोजित किया गया तथा उन्हें संबंधित उद्योग का भ्रमण भी कराया गया। औद्योगिक भ्रमण के दौरान अभ्यर्थियों ने सुरक्षा प्रणालियों, कैमरा इंस्टॉलेशन, नेटवर्किंग, रखरखाव और आधुनिक निगरानी तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की।

सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर मूल्यांकन

सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर ट्रेड के प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें सिलाई कौशल, माप लेने की तकनीक, परिधान निर्माण, फिनिशिंग और गुणवत्ता मानकों के आधार पर प्रतिभागियों की दक्षता का परीक्षण किया गया। यह मूल्यांकन प्रतिभागियों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

पाइप फिटर मूल्यांकन

पाइप फिटर (ऑयल एंड गैस/सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) ट्रेड के प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया। इस प्रक्रिया में गैस पाइपलाइन इंस्टॉलेशन, सुरक्षा उपायों, उपकरणों के उपयोग और तकनीकी दक्षता का परीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करना था।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी प्रशिक्षुओं एवं कर्मचारियों के लिए योग सत्र आयोजित किया गया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही नियमित योग के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया।

विश्व युवा कौशल दिवस

विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को कौशल विकास के महत्व से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में प्रेरणादायक सत्र, विशेषज्ञों के व्याख्यान, करियर मार्गदर्शन और स्वरोजगार के अवसरों पर चर्चा की गई। इस आयोजन ने प्रतिभागियों को अपने कौशल का विकास कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

प्रतिभागियों की सुरक्षा तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से अग्नि सुरक्षा अभ्यास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अग्निशमन यंत्रों के उपयोग, आग लगने की स्थिति में सुरक्षित निकासी, प्राथमिक प्रतिक्रिया और सुरक्षा मानकों की जानकारी व्यावहारिक रूप से दी गई।

यह परियोजना 'कुशल भारत, आत्मनिर्भर भारत' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को मजबूत कर रही है। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, औद्योगिक अनुभव और प्रमाणन के माध्यम से युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भविष्य में भी अधिक से अधिक युवाओं को कौशल, सम्मानजनक आजीविका और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।■

सहकार की सवारी, समृद्धि की तैयारी

25 शहरों में पहुंची भारत टैक्सी, 8.27 लाख सारथियों को मिली कमीशन से मुक्ति और मालिकाना हक

दो वर्षों में 500 शहरों तक विस्तार का लक्ष्य- अमित शाह

युवा सहकार टीम

देश के ऐप आधारित टैक्सी बाजार में लंबे समय से निजी एग्रीगेटर कंपनियों का दबदबा रहा है। इन प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले ड्राइवरों की सबसे बड़ी शिकायत किराये में भारी कमीशन, भुगतान से जुड़ी अनिश्चितता, खाते को अचानक बंद किए जाने और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी न मिलने की रही है। इन्हीं समस्याओं के सहकारी समाधान के रूप में शुरू हुई 'भारत टैक्सी' अब तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार कर रही है।

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित भारत टैक्सी दिल्ली-एनसीआर से आगे बढ़ते हुए गुजरात के 14 शहरों, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, नवी मुंबई, जयपुर, कानपुर और पुणे सहित लगभग 25 शहरी क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। अगले चरण में नागपुर, कोलकाता, रांची, पटना, गुवाहाटी, भोपाल और इंदौर में सेवाएं शुरू करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में इस चालक स्वामित्व वाले डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म को देश के 500 से अधिक शहरों और कस्बों तक पहुंचाना है।

भारत टैक्सी के विस्तार के साथ इससे जुड़ने वाले ड्राइवर-पार्टनरों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 28 जुलाई, 2026 तक देशभर में 8.27 लाख ड्राइवर-पार्टनर, जिन्हें प्लेटफॉर्म 'सारथी' कहता है, इससे जुड़ चुके हैं। इनमें दिल्ली-एनसीआर के 2.61 लाख, गुजरात के 1.04 लाख और महाराष्ट्र के 84,332 सारथी शामिल हैं।

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी पहचान इसका जीरो-कमीशन मॉडल है। इसके अंतर्गत यात्री द्वारा किसी सवारी के लिए दिया गया किराया बिना किसी कमीशन कटौती के सीधे चालक को मिलता है। तकनीकी संचालन, मोबाइल एप के रखरखाव और प्लेटफॉर्म के विस्तार के लिए सारथियों से मामूली सदस्यता या प्लेटफॉर्म उपयोग शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक सवारी के किराये में से प्रतिशत के आधार पर कमीशन काटने का प्रावधान नहीं है।

यही व्यवस्था भारत टैक्सी को निजी टैक्सी

एग्रीगेटर कंपनियों से अलग बनाती है। निजी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर केवल सेवा प्रदाता या गिग वर्कर होते हैं, जबकि भारत टैक्सी में उन्हें सहकारी संस्था के सदस्य और हिस्सेदार के रूप में शामिल किया जाता है। इसीलिए यहां चालक को 'ड्राइवर' के बजाय 'सारथी' कहा गया है। यह केवल नाम का परिवर्तन नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म की पूरी कार्यप्रणाली और सोच में बदलाव का प्रतीक है।

सारथी केवल ड्राइवर नहीं, संस्था के मालिक भी

भारत टैक्सी के सहकारी स्वरूप को रेखाद्यंकित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले सारथी केवल वाहन चालक नहीं, बल्कि सहकारी संस्था के हिस्सेदार और मालिक भी हैं। भारत टैक्सी का उद्देश्य सारथियों को अधिक कमाई देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा, स्वामित्व और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता उपलब्ध कराना भी है। आने वाले समय में यह सहकारी संस्था ड्राइवरों को कर्ज देने, बीमा सुरक्षा देने और उनके कारोबार के विस्तार में सहयोग करने का काम भी करेगी। भारत टैक्सी को बहुराज्यीय सहकारी समिति के रूप में संचालित किया जा रहा है।

25 शहरों तक विस्तार

भारत टैक्सी की शुरुआत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से की गई थी। इसके बाद गुजरात को भारत टैक्सी के बड़े परिचालन केंद्र के रूप में विकसित किया गया। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, द्वारका, वडोदरा, राजकोट, सोमनाथ, वलसाड, आनंद, जामनगर, भावनगर, नडियाद, जूनागढ़, मेहसाणा और अमरेली सहित 14 शहरों में भारत टैक्सी की सेवाएं शुरू की गई। इसके बाद मुंबई और नवी मुंबई में 24 जुलाई और इसके अगले दिन 25 जुलाई को जयपुर में इसकी सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया गया। मुंबई और नवी मुंबई जैसे बड़े आर्थिक केंद्र में प्रवेश भारत टैक्सी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां टैक्सी और ऐप आधारित परिवहन सेवाओं की मांग बहुत अधिक है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, व्यावसायिक केंद्रों और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए चालक-स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म निजी कंपनियों का मजबूत विकल्प बन सकता है। जयपुर में सेवा की शुरुआत से राजस्थान के पर्यटन और शहरी परिवहन क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। स्थानीय टैक्सी चालकों और ऑटो ड्राइवरों को सहकारी मॉडल से जोड़ने पर उनकी कमाई में होने वाली कमीशन कटौती घट सकती है। साथ ही यात्रियों को पारदर्शी किराये और स्थानीय स्तर पर जवाबदेह सेवा मिल सकती है।

इन शहरों के अलावा लखनऊ, चंडीगढ़, कानपुर और पुणे में भी भारत टैक्सी का विस्तार किया गया है। अगला चरण पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत पर केंद्रित होगा, जिसमें कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, भोपाल, इंदौर और नागपुर जैसे शहर शामिल हैं।

कमीशन कटौती से मिली मुक्ति

ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं से जुड़े ड्राइवरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रत्येक सवारी पर काटा जाने वाला कमीशन रहा है। कई बार यह कमीशन चालक की कुल किराया आय का बड़ा हिस्सा बन जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की शर्तें, वाहन संचालन की लागत, ईंधन मूल्य और

भारत टैक्सी की शुरुआत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से की गई थी। इसके बाद गुजरात को भारत टैक्सी के बड़े परिचालन केंद्र के रूप में विकसित किया गया। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, द्वारका, वडोदरा, राजकोट, सोमनाथ, वलसाड, आनंद, जामनगर, भावनगर, नडियाद, जूनागढ़, मेहसाणा और अमरेली सहित 14 शहरों में भारत टैक्सी की सेवाएं शुरू की गई। इसके बाद मुंबई और नवी मुंबई में 24 जुलाई और इसके अगले दिन 25 जुलाई को जयपुर में इसकी सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

ग्राहकों का भरोसा सबसे बड़ी कसौटी

भारत टैक्सी के सामने अवसर बड़े हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। देश के ऐप आधारित टैक्सी बाजार में पहले से स्थापित कंपनियों के पास बड़ा ग्राहक आधार, उन्नत तकनीक, व्यापक वाहन नेटवर्क और भारी निवेश क्षमता है। भारत टैक्सी को इनके मुकाबले समय पर वाहन उपलब्ध कराने, ऐप की तकनीकी विश्वसनीयता बनाए रखने, ग्राहक सहायता मजबूत करने और सेवा की गुणवत्ता में निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी।

सारथियों को अधिक कमाई और मालिकाना हक देने का मॉडल तभी सफल होगा, जब यात्रियों को भी सुरक्षित, समयबद्ध और सुविधाजनक सेवा मिले। ग्राहक केवल कम किराये के आधार पर किसी प्लेटफॉर्म से लंबे समय तक नहीं जुड़ते। ड्राइवर का व्यवहार, वाहन की स्थिति, बुकिंग की उपलब्धता, शिकायत का समाधान और डिजिटल भुगतान की सुगमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

करीब आठ लाख सारथियों, 25 शहरों के नेटवर्क और 500 शहरों तक पहुंचने की महत्वाकांक्षी योजना के साथ भारत टैक्सी ने देश के मोबिलिटी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अब इसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि यह सहकारी प्लेटफॉर्म सारथियों की आय और अधिकारों की रक्षा करते हुए यात्रियों को कितनी विश्वसनीय, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करा पाता है।

28 जुलाई 2026 तक भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म पर कुल 8.27 लाख सारथियों यानी चालकों का पंजीकरण किया गया है। उपलब्ध राज्यवार आंकड़ों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में सर्वाधिक 2,61,045 चालक पंजीकृत हैं। गुजरात में 1,04,163, महाराष्ट्र में 84,332, उत्तर प्रदेश में 21,621, राजस्थान में 20,599 और चंडीगढ़ में 10,695 चालक जुड़े हैं। इनमें कैब, ऑटो और बाइक चालक शामिल हैं।

ऋण की किस्तें ड्राइवरों की वास्तविक कमाई को और कम कर देती हैं। भारत टैक्सी का जीरो कमीशन मॉडल इसी समस्या को दूर करता है। प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की गई सवारी का पूरा किराया सारथी को मिलने से चालक की प्रति सवारी आय बढ़ रही है।

भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म पर 8.27 लाख चालक पंजीकृत

28 जुलाई 2026 तक भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म पर कुल 8.27 लाख सारथियों यानी चालकों का पंजीकरण किया गया है। उपलब्ध राज्यवार आंकड़ों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में सर्वाधिक 2,61,045 चालक पंजीकृत हैं। गुजरात में 1,04,163, महाराष्ट्र में 84,332, उत्तर प्रदेश में 21,621, राजस्थान में 20,599 और चंडीगढ़ में 10,695 चालक जुड़े हैं। इनमें कैब, ऑटो और बाइक चालक शामिल हैं। सरकार ने भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म की स्थापना या विस्तार के लिए कोई वित्तीय सहायता, इक्विटी सहयोग अथवा प्रोत्साहन नहीं दिया है। प्लेटफॉर्म का संचालन सहकारी संरचना के तहत सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

बीमा, ऋण और वाहन वित्तपोषण की तैयारी

भारत टैक्सी की योजना केवल टैक्सी बुकिंग सेवा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। यह प्लेटफॉर्म सारथियों को स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, संस्थागत ऋण और वाहन वित्तपोषण जैसी सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रहा है। सारथियों को रियायती दरों पर बीमा उपलब्ध कराने के अलावा एसबीआई मुद्रा ऋण और अन्य बैंकिंग योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे नया वाहन खरीदने, मौजूदा वाहन को उन्नत करने या अपने परिवहन व्यवसाय का विस्तार करने के इच्छुक चालकों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से सहायता मिल सकेगी।

भारत टैक्सी के सारथियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें मोबाइल ऐप एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, ग्राहक सेवा, सड़क सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, व्यवहार कौशल और शिकायतों के समाधान से संबंधित प्रशिक्षण शामिल है। इसका उद्देश्य भारत टैक्सी को केवल कम किराये वाला प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि गुणवत्ता और सुरक्षा के आधार पर विश्वसनीय परिवहन सेवा बनाना है।

हवाई अड्डों, मेट्रो, रेलवे, नगर निकायों और यातायात प्रबंधन संस्थाओं के साथ समझौते करके भारत टैक्सी की परिचालन पहुंच बढ़ाने की भी योजना है। गुजरात में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की राजकोट और सूरत इकाइयों, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद नगर निगम, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, गुजरात राज्य सहकारी बैंक, अदानी एयरपोर्ट, गुजरात ट्रैफिक पुलिस, पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल और वडोदरा एयरपोर्ट जैसे संस्थानों के साथ सहयोग की पहल की गई है।■

कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट 29 देशों तक पहुंचा

युवा सहकार टीम

भारत का सहकारिता क्षेत्र अब गांवों और घरेलू बाजार की सीमाओं से निकलकर वैश्विक व्यापार में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। सहकारी समितियों द्वारा तैयार कृषि और अन्य उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए गठित नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यानी एनसीईएल इस दिशा में एक प्रमुख अम्ब्रेला संगठन के रूप में काम कर रहा है। अपनी स्थापना के बाद से एनसीईएल ने 29 देशों में 54 विभिन्न उत्पादों का निर्यात किया है। वित्त वर्ष 2025-26 तक एनसीईएल ने कुल 5,731 करोड़ रुपये का निर्यात कारोबार किया।

एनसीईएल केवल निर्यात करने वाली संस्था नहीं है। यह सहकारी समितियों को उत्पादों की खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, प्रमाणन और अंतरराष्ट्रीय विपणन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। इसके माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स को भी वैश्विक मूल्य शृंखला से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एनसीईएल से पैक्स सहित 16,002 सहकारी समितियां जुड़ चुकी हैं। संस्था ने लगभग 14.08 लाख टन कृषि उत्पादों का निर्यात किया है। कृषि श्रेणी के 40 उत्पादों का निर्यात मूल्य 5,651.03 करोड़ रुपये से अधिक रहा। जबकि कृषि और अन्य श्रेणियों को मिलाकर कुल 54 उत्पादों का निर्यात 5,731 करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है।

एनसीईएल के निर्यात कारोबार में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में संस्था ने 2.66 लाख टन उत्पादों का निर्यात किया था, जिसका मूल्य 1,113.13 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात बढ़कर 10.83 लाख टन और इसका मूल्य 4,283.56 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान संस्था ने 122 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया और सदस्य सहकारी समितियों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 20 प्रतिशत लाभांश भी दिया।

एनसीईएल ने 2025-26 में किया 5,731 करोड़ रुपये का निर्यात

एनसीईएल के निर्यात पोर्टफोलियो में बासमती और गैर-बासमती चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, चीनी, प्याज, जीरा, मसाले, चाय, फल-सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, बेबी फूड, पशु उत्पाद और समुद्री उत्पाद शामिल हैं। जलीय कृषि और झींगा निर्यात के लिए यह मर्चेंट एक्सपोर्टर के रूप में भी काम कर रहा है।

इस सहकारी संस्था ने सेनेगल, इंडोनेशिया और नेपाल के 61 आयातकों के साथ रणनीतिक समझौते किए हैं। इसके अलावा विदेशी एजेंसियों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और सहकारी संस्थाओं के साथ भी साझेदारी की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों के माध्यम से भारतीय सहकारी उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशे जा रहे हैं।

सहकारी कृषि निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एनसीईएल ने एपीडी के साथ भी समझौता किया है। इसके तहत सहकारी समितियों को निर्यात गुणवत्ता मानकों, खाद्य सुरक्षा, दस्तावेजी प्रक्रिया, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और उत्पाद आधारित निर्यात रणनीति का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

एनसीईएल ने अफ्रीका, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात और एशियाई देशों में निर्यात विस्तार का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संस्था के लिए दीर्घकाल में दो लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी प्रगति से स्पष्ट है कि बेहतर प्रसंस्करण, पैकेजिंग, प्रमाणन और बाजार संपर्क के जरिए गांवों की सहकारी समितियां भी वैश्विक व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती हैं।

श्वेत क्रांति की धरती से शुरू हुई सहकारी शिक्षा की नई क्रांति

सहकार से रोजगार और समृद्धि की राह दिखा रहा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय

17 लाख प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता वाला सहकारिता क्षेत्र रोजगार और ग्रामीण समृद्धि का नया केंद्र बनेगा- मुरलीधर मोहोल

युवा सहकार टीम

देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के पहले बैच को शत-प्रतिशत प्लेसमेंट मिला है। यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने शिरकत की। यह आयोजन विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने का आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह भारत के सहकारी आंदोलन में पेशेवर शिक्षा, रोजगार और युवा नेतृत्व के नए अध्याय की शुरुआत बन गया। विश्वविद्यालय के पहले बैच के सभी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिलना इस बात का प्रमाण है कि सहकारी प्रबंधन, कृषि व्यवसाय, ग्रामीण वित्त और विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। गुजरात के आणंद स्थित इस यूनिवर्सिटी का प्रथम दीक्षांत समारोह केवल विश्वविद्यालय की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है, जिसमें शिक्षित युवा किसानों के साथ खड़े होंगे, सहकारी संस्थाओं को आधुनिक बनाएंगे और गांवों को आर्थिक विकास के सक्रिय केंद्रों में बदलेंगे।

दीक्षांत समारोह में 302 विद्यार्थियों को स्नातक और दो शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। यह सफलता बताती है कि सहकारी शिक्षा अब केवल सामाजिक सेवा या ग्रामीण विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए प्रतिष्ठित, रोजगारपरक और दीर्घकालिक करियर का मजबूत माध्यम बन रही है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका औपचारिक शिक्षण आज पूरा हो रहा है, लेकिन वास्तविक कार्यक्षेत्र में आपकी नई यात्रा अब प्रारंभ हो रही है। आपको अपने

ज्ञान, कौशल और नवाचार का उपयोग समाज, किसानों और सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए करना है।

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के पहले बैच के सभी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिलना सामान्य शैक्षणिक उपलब्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह परिणाम सहकारी क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं और आधुनिक प्रबंधन में प्रशिक्षित युवाओं की बढ़ती मांग को दर्शाता है। सहकारी संस्थाओं को अब ऐसे पेशेवरों की आवश्यकता है, जो सहकारिता के सामाजिक उद्देश्यों को समझने के साथ वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल तकनीक, विपणन, आपूर्ति शृंखला, ग्रामीण ऋण, कृषि व्यवसाय और कॉरपोरेट प्रशासन में भी दक्ष हों। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सहकारी बैंकिंग, ग्रामीण विकास, कृषि विपणन, डेयरी प्रबंधन, आपूर्ति शृंखला, वित्तीय सेवाओं और उद्यम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अवसर मिले हैं। शत-प्रतिशत प्लेसमेंट से ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं के लिए भी सकारात्मक संदेश गया है। अब उन्हें बेहतर रोजगार के लिए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग होने की जरूरत नहीं है। वे आधुनिक प्रबंधन शिक्षा प्राप्त कर सहकारी संस्थाओं, कृषि व्यवसायों और ग्रामीण उद्यमों में सम्मानजनक करियर बना सकते हैं। इसके साथ ही वे अपने ज्ञान और अनुभव का लाभ अपने गांवों, किसानों और स्थानीय समुदायों तक पहुंचा सकते हैं।

सहकारी शिक्षा की नई क्रांति

आणंद की धरती भारत की श्वेत क्रांति की जन्मभूमि रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रेरणा से त्रिभुवनदास पटेल ने वर्ष 1946 में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना की थी। उन्होंने किसानों और पशुपालकों को संगठित कर उन्हें अपने उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन का स्वामी बनने का मार्ग दिखाया। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का नाम सहकारिता के इसी महान पुरोधा त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर रखा गया है। यह विश्वविद्यालय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद (इरमा) की लगभग 45 वर्षों की समृद्ध अकादमिक और संस्थागत विरासत पर आधारित है।

17 लाख युवाओं के लिए खुलेंगे अवसर

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि आने वाले समय में देश के सहकारिता क्षेत्र को 17 लाख से अधिक प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता होगी। 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय इस जरूरत को पूरा करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। देश में वर्तमान में 8.50 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 32 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। इस प्रकार देश की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहकारिता क्षेत्र का हिस्सा है।

अब सहकारी मॉडल जैविक खेती, बीज उत्पादन, निर्यात, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं, परिवहन और प्लेटफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था जैसे नए क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रहा है। ■

एआई से बदलेगी कृषि और सहकारिता की कार्यप्रणाली

मुरलीधर मोहोल ने विद्यार्थियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नवाचार का उपयोग कर सहकारी संस्थाओं एवं कृषि व्यवसायों को आधुनिक बनाने का आह्वान किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण के माध्यम से फसलों की मांग, बाजार मूल्य, मौसम के जोखिम और उत्पादन की संभावनाओं का बेहतर आकलन किया जा सकता है। किसानों को यह जानकारी मिल सकती है कि किस फसल की बुवाई लाभदायक होगी, उपज को कब बेचना उचित रहेगा और किस बाजार में बेहतर कीमत उपलब्ध है। डिजिटल तकनीक सहकारी समितियों के लेखाद्यकन, सदस्यता रिकॉर्ड, ऋण वितरण और खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता बढ़ा सकती है।

इससे गड़बड़ियों की आशंका कम होगी और सरकारी योजनाओं एवं सहकारी सुविधाओं का लाभ सही सदस्य तक पहुंच सकेगा। प्रशिक्षित युवा कृषि उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स के माध्यम से छोटे किसानों के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध करा सकते हैं। जैविक उत्पादों, स्थानीय खाद्य पदार्थों और ग्रामीण हस्तशिल्प को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर गांवों में नए रोजगार भी तैयार किए जा सकते हैं।

आणंद की धरती भारत की श्वेत क्रांति की जन्मभूमि रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रेरणा से त्रिभुवनदास पटेल ने वर्ष 1946 में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना की थी। उन्होंने किसानों और पशुपालकों को संगठित कर उन्हें अपने उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन का स्वामी बनने का मार्ग दिखाया। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का नाम सहकारिता के इसी महान पुरोधा त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर रखा गया है।

भविष्य उन्हीं का है जो सीखते हैं, बदलते हैं और नवाचार करते हैं

स्किल इंडिया 2.0 की नई उड़ान, भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रहा भारत का युवा

530 करोड़ रुपये के प्रस्तावित स्किल्स आउटकम्स फंड से दो लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण, रोजगार और आजीविका से जोड़ने का लक्ष्य

युवा सहकार टीम

'भविष्य उन्हीं का है जो निरंतर सीखते हैं, बदलते परिवेश के अनुरूप स्वयं को ढालते हैं और नवाचार करने का साहस रखते हैं।' विश्व युवा कौशल दिवस (15 जुलाई) 2026 के अवसर पर कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी का यह संदेश केवल एक प्रेरक कथन नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण की नई कार्ययोजना का आधार भी है। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ऑटोमेशन और नई तकनीकों के दौर में यह स्पष्ट हो चुका है कि भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि कुशल मानव संसाधन होगा। भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

नई दिल्ली स्थित कौशल भवन में आयोजित विश्व युवा कौशल दिवस 2026 समारोह में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने कई ऐसी महत्वाकांक्षी पहलों की घोषणा की, जो देश के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को अगले स्तर तक ले जाने का रोडमैप पेश करती हैं। इन पहलों का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।

कौशल विकास: डिग्री से आगे, आजीवन सीखने की संस्कृति

आज दुनिया तेजी से बदल रही है। कई पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो रही हैं, जबकि नई तकनीकों पर आधारित रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में कौशल विकास को केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। भारत के युवाओं को केवल वर्तमान की जरूरतों के अनुरूप नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के लिए भी तैयार रहना होगा। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिताएं, उत्कृष्टता केंद्र, अप्रेंटिसशिप और उद्योगों के साथ मजबूत साझेदारी युवाओं को वैश्विक अवसरों से

जोड़ने का माध्यम बन रही हैं। जयंत चौधरी ने महिलाओं से गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि समावेशी विकास के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा।

इंडिया स्किल्स 2026-27: प्रतिभाओं के लिए राष्ट्रीय मंच

समारोह की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2026-27 के दिशा-निर्देश जारी करना शामिल रहा। 63 उद्योग-संबद्ध कौशल श्रेणियों में आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता देश की सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता है। इसके माध्यम से देशभर के युवा अपनी तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन कर सकेंगे और उत्कृष्ट प्रतिभाओं को वर्ल्डस्किल्स जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे देश के किसी भी हिस्से का युवा आसानी से इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकता है। यह डिजिटल व्यवस्था कौशल विकास को अधिक पारदर्शी, सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

दुनिया में बढ़ रहा भारत के कौशल का सम्मान

भारत के युवा अब केवल देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 और ताइपे कैपिटल कप 2026 में भारतीय प्रतिभागियों ने तीन स्वर्ण, तीन रजत, एक कांस्य पदक और तीन मेरिट पुरस्कार जीतकर यह साबित कर दिया है कि भारतीय युवाओं की तकनीकी दक्षता विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। यह उपलब्धियां स्किल इंडिया अभियान की बढ़ती प्रभावशीलता और भारतीय प्रशिक्षण प्रणाली की गुणवत्ता का प्रमाण हैं।

भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार होगा भारत

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल इंडिया के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इन केंद्रों में आधुनिक प्रयोगशालाएं, अत्याधुनिक मशीनें, एआई आधारित प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और वैश्विक मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे।

इनका उद्देश्य युवाओं को केवल प्रमाणपत्र देना नहीं, बल्कि उन्हें उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है, ताकि प्रशिक्षण पूरा होते ही रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकें।

स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में रोजगार का नया द्वार

केंद्रीय बजट 2026-27 में 1.5 लाख देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की घोषणा को धरातल पर उतारते हुए मंत्रालय ने बहु-कुशल देखभालकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत 1.3 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पहल से स्वास्थ्य सेवा, वृद्धजन देखभाल और घरेलू देखभाल सेवाओं में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

परिणाम आधारित वित्त पोषण का नया मॉडल

समारोह की सबसे महत्वाकांक्षी घोषणाओं में लगभग 530 करोड़ रुपये के प्रस्तावित स्किल्स आउटकम्स फंड की शुरुआत भी शामिल है। यह परिणाम-आधारित वित्तपोषण मॉडल सरकारी सहायता, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और परोपकारी निवेश को एक मंच पर लाएगा। इस पहल के माध्यम से दो लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण, रोजगार और आजीविका से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। फंडिंग को प्रमाणन, रोजगार, नौकरी में बने रहने और वास्तविक परिणामों से जोड़कर प्रशिक्षण संस्थानों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी।■

महिलाओं को मिलेगा कौशल विकास में नेतृत्व

विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं। मंत्रालय ने लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति प्रशिक्षण से लेकर रोजगार, अप्रेंटिसशिप, कार्यस्थल पर टिकाव और करियर उन्नति तक महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं की पहचान कर समाधान तैयार करेगी। साथ ही महिलाओं के कौशल विकास और रोजगार से जुड़े सफल मॉडलों का राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा, ताकि राज्यों और संस्थानों के बीच बेहतर अनुभवों का आदान-प्रदान हो सके।

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF EDUCATION
Government of India
सत्यमेव जयते

nbt.india
एकः सूते सकलम्
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
Ministry of Education, Government of India

CHINAR BOOK FESTIVAL 3rd EDITION SKICC, Srinagar

चिनार पुस्तक महोत्सव

साथ पढ़ेगा, साथ बढ़ेगा कश्मीर :
तृतीय चिनार पुस्तक महोत्सव में दिखा साहित्य, संवाद और युवा हिस्सेदारी का संगम

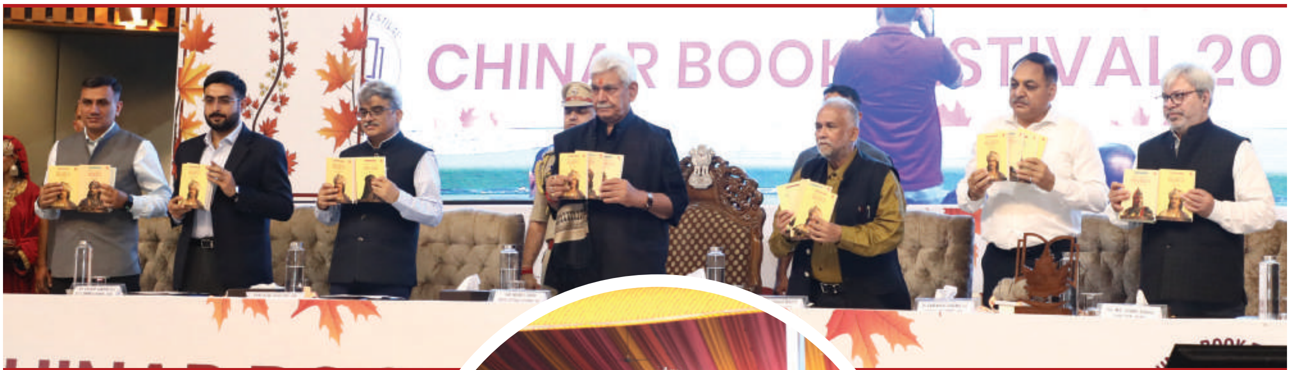

तीसरे चिनार पुस्तक महोत्सव का रविवार 26 जुलाई को भव्य समापन हुआ। नौ दिनों तक चले इस साहित्यिक महोत्सव ने श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (एसकेआईसीसी) में कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आए पुस्तक प्रेमियों, विद्यार्थियों और कश्मीर घाटी के आम जन की उत्साहवर्धक हिस्सेदारी देखने को मिली। सप्ताह के विभिन्न कार्यदिवसों में जहां प्रतिदिन लगभग 57,000 से 73,000 तक की संख्या में लोग आए, वहीं सप्ताहांत में आने वाले लोगों का आंकड़ा 1,00,000 पार कर गया। यह प्रमाण है कि यह कश्मीर का सबसे बड़ा साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्सव बन गया है।

शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा जिला प्रशासन, श्रीनगर तथा राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल) के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में 200 से अधिक प्रकाशकों, 800 से अधिक कलाकारों और लेखकों तथा हजारों विद्यार्थियों, पाठकों और आमजन ने भाग लिया। 'मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर बढ़ेंगे' विषय पर आधारित इस आयोजन ने नौ दिनों तक श्रीनगर को विचार, संस्कृति और सामाजिक संवाद का जीवंत केंद्र बनाए रखा।

महोत्सव का उद्घाटन 18 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने किया। उन्होंने इसे क्षेत्र में शांति, परिवर्तन और आत्मविश्वास का प्रतीक बताते हुए युवाओं से पढ़ने और लिखने को साप्ताहिक आदत बनाने का आह्वान किया।

उद्घाटन समारोह में वर्ष 2025 में आयोजित गोजरी अनुवाद कार्यशाला के अंतर्गत प्रकाशित 24 द्विभाषी पुस्तकों, राजतरंगिणी संवाद पहल के अंतर्गत कल्हण की 12वीं शताब्दी की कालजयी कृति पर आधारित पाँच उपन्यासों, तथा 'जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज' के उर्दू अनुवाद का लोकार्पण भी किया गया। राजतरंगिणी पर आधारित किशोर उपन्यास शृंखला 'राजतरंगिणी की कहानियां' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत की ओर से सांस्कृतिक-ऐतिहासिक धरोहरों एवं ज्ञान परंपरा के प्रति जागरुकता बढ़ाने की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इन उपन्यासों की रचना प्रक्रिया में द्वितीय चिनार पुस्तक महोत्सव वर्ष 2025 में आयोजित राजतरंगिणी कार्यशाला महत्वपूर्ण पड़ाव रही। कार्यशाला के अंतर्गत कल्हण कृत राजतरंगिणी के विशिष्ट पात्रों में रानी यशोवती, अवंतिवर्मा, ललितादित्य, मातृगुप्त, रानी दिद्दा, नर-किन्नर, जयापीड, जय सिंह एवं कोटा रानी जैसे विशिष्ट पात्रों पर लिखे जाने वाले उपन्यासों पर चर्चा की गई।

उपर्युक्त शृंखला के प्रथम चरण में सम्राट ललितादित्य, रानी यशोवती, महाराज जयापीड, मातृगुप्त एवं कोटा रानी पर केंद्रित उपन्यासों का माननीय राज्यपाल जम्मू-कश्मीर मनोज सिन्हा जी के हाथों लोकार्पण किया गया। इन उपन्यासों में उल्लिखित राजा अथवा रानी के जीवन काल, संघर्ष, चुनौतियों के साथ ही तत्कालीन समाज, संस्कृति एवं परिवेश भी उसी गहनता के साथ प्रस्तुत किया गया है। जिससे किशोर एवं युवा पाठक कश्मीर के गौरवशाली इतिहास एवं समाज से सरल एवं सुग्राह्य भाषा में परिचित हो सकें। यह केवल प्रारंभ है। इसके अगले चरणों में कश्मीर के अन्य शासकों पर भी उपन्यास पाठकों के बीच होंगे।

चिनार पुस्तक महोत्सव के तीसरे संस्करण का प्रमुख आकर्षण साहित्यिक परिचर्चाओं और संवाद सत्रों की समृद्ध शृंखला रही, जिसमें देश की जानी मानी शख्सियतों के साथ विशेष संवाद आयोजित किए गए। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एसी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) तक की अपनी प्रेरणादायक यात्रा साझा करते हुए विद्यार्थियों से अनुशासन और जिज्ञासा, दोनों को समान महत्व देने का आह्वान किया। वरिष्ठ अभिनेता राकेश बेदी ने अपने हास्यपूर्ण और प्रेरणादायक संबोधन के माध्यम से विद्यार्थियों को जुनून के साथ रचनात्मक क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं, फिल्म निर्माता इम्तियाज अली ने कहानी कहने की कला, आध्यात्मिकता और सिनेमा पर आयोजित आत्मीय सत्र में अपनी फिल्मों से जुड़े अनेक व्यक्तिगत अनुभव साझा कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

ऑथर्स कॉर्नर में आयोजित समूह चचाओं ने कश्मीर की पहचान को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का अवसर प्रदान किया। इनमें पत्रकारिता और कहानी कहने की बदलती प्रकृति, उर्दू और कश्मीरियत के साझा सांस्कृतिक संबंधों पर विचार-विमर्श हुआ। कश्मीरी रंगमंच के पुनरुत्थान, घाटी की साहित्यिक सौंदर्य-दृष्टि के विकास, पारंपरिक हस्तशिल्प एवं परिधानों के संरक्षण, कश्मीर की भाषाओं और साहित्यिक विरासत के संवर्धन तथा साहित्य एवं डिजिटल नवाचार के माध्यम से कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था की नई संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

महोत्सव के आठवें दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई, जब 4,644 से अधिक विद्यार्थियों ने डल झील के किनारे आयोजित 5 किलोमीटर रीडिंग मैराथन में भाग लिया। इस आयोजन को माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 'पठन-पाठन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मैराथन में सर्वाधिक बच्चों की भागीदारी' के लिए इस कार्यक्रम ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में नया कीर्तिमान स्थापित किया।

पूरे महोत्सव के दौरान चिल्ड्रन्स कॉर्नर गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रहा। यहाँ कहानी-वाचन, कठपुतली नाटक, सुलेख (कैलिग्राफी), हस्तशिल्प कार्यशालाएं तथा प्रतिदिन राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय से परिचित करवाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें प्रतिदिन हजारों बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नौ दिनों तक प्रत्येक शाम रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सराबोर रही, जिनमें रौफ नृत्य, कश्मीरी लोक रंगमंच, सूफियाना संगीत, मुशायरे तथा घाटी के विभिन्न कलाकारों की संगीतमय प्रस्तुतियाँ शामिल थीं।

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर महोत्सव के अंतिम दिन सुप्रसिद्ध नाटककार राकेश रोशन भट्ट द्वारा लिखित नाटक 'मरकर जीना' का प्रभावशाली मंचन किया गया, जिसने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद सुधाकर मराठे ने कहा कि इस महोत्सव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना को साकार करते हुए शिक्षा को क्लासरूम से बाहर ले जाकर घाटी के युवाओं में पुस्तकों और ज्ञान के प्रति आजीवन प्रेम विकसित करने का कार्य किया है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के निदेशक श्री युवराज मलिक ने चिनार पुस्तक महोत्सव को कश्मीर की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत का 'ब्रांड एम्बेसडर' बताते हुए कहा कि इस महोत्सव ने घाटी में साहित्यिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

चिनार पुस्तक महोत्सव के मुख्य संयोजक डॉ. अमित वांचू ने कहा कि श्रीनगर सहित जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों से आए आम जन का सहयोग और हिस्सेदारी अपेक्षा से कहीं अधिक रही। अब श्रीनगर चौथे संस्करण की ओर आशाभरी निगाह से देख रहा है, उस संकल्प के साथ जो इन नौ दिनों में और अधिक दृढ़ हुआ है। कश्मीर पढ़ता रहेगा और साथ मिलकर आगे बढ़ता रहेगा।

बिहार बनेगा ग्लोबल स्किल हब

महिलाओं की ताकत और युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान, एनएसटीआई (महिला) के स्थायी परिसर और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से बिहार के कौशल विकास को मिलेगी नई दिशा

युवा सहकार टीम

भारत की विकास यात्रा में अब कौशल विकास केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्रांति और अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार की बढ़ती मांग के बीच भारत अपने युवाओं को विश्वस्तरीय कौशल से लैस करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में बिहार में शुरू हुई दो नई पहल राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (महिला), पटना के स्थायी परिसर और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी), पटना राज्य के कौशल विकास परिदृश्य में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत हैं।

ये दोनों परियोजनाएं केवल नए संस्थानों की स्थापना भर नहीं हैं, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार के अवसर और बिहार को देश के प्रमुख कौशल केंद्र के रूप में विकसित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और बिहार सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वर्षों में बिहार केवल कुशल मानव संसाधन तैयार नहीं करेगा, बल्कि वैश्विक कार्यबल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी बनेगा।

कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि महिला-नेतृत्व वाला विकास विकसित भारत की आधारशिला है। एनएसटीआई (महिला) का स्थायी परिसर महिलाओं को आधुनिक अधोसंरचना, उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण और नए अवसरों से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बिहार के युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करेगा और उन्हें विदेशों में सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल बिहार के कार्यबल को अधिक प्रतिस्पर्धी और आत्मविश्वासी बनाएगी।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन दोनों परियोजनाओं को बिहार के कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए परिवर्तनकारी बताया। उनके अनुसार, आधुनिक एनएसटीआई (महिला) परिसर राज्य की युवा महिलाओं को

गुणवत्तापूर्ण और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण देगा, जबकि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बिहार के युवाओं को वैश्विक रोजगार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेगा। उन्होंने कहा कि इन पहलों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भरता, आधुनिक कौशल और अंतरराष्ट्रीय अवसरों से जोड़ा जाएगा, जिससे ՚समृद्ध बिहार՚ और ՚विकसित भारत՚ के साझा संकल्प को नई गति मिलेगी।

महिलाओं के कौशल विकास को आधुनिक आधार

बिहार में महिलाओं के लिए केंद्र सरकार का एकमात्र विशेष कौशल प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (महिला), पटना अब अपने स्थायी परिसर में विकसित होगा। बिहटा के सिकंदरपुर में लगभग 99.97 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह आधुनिक परिसर महिलाओं के लिए उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण का नया केंद्र बनेगा। इस परिसर में अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन, आधुनिक शैक्षणिक परिसर, प्रयोगशालाएं और छात्रावास जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और नई तकनीकों पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे।

भविष्य की नौकरियों के अनुरूप होंगे नए पाठ्यक्रम

नई अर्थव्यवस्था में केवल पारंपरिक कौशल पर्याप्त नहीं हैं। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित परिसर में शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत 13 आधुनिक ट्रेड संचालित किए जाएंगे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्रोन तकनीशियन, सौर तकनीशियन, रेडियोलॉजी तकनीशियन जैसे भविष्य की मांग वाले क्षेत्रों के पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिवर्ष 435 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता विकसित की जाएगी। यह पहल इस बात का संकेत है कि कौशल विकास अब केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं और चौथी औद्योगिक क्रांति के अनुरूप कार्यबल तैयार करेगा।

दुनिया तक पहुंचेगा बिहार का हुनर

बिहार के लाखों युवा वर्षों से विदेशों में रोजगार की संभावनाओं की तलाश करते रहे हैं। हालांकि भाषा, प्रमाणन और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं का समाधान बनने जा रहा है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एसआईआईसी)। करीब 7 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश से स्थापित होने वाला यह केंद्र बिहार के युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार का प्रवेशद्वार बनेगा। यहां अंग्रेजी, जर्मन, जापानी और फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही अंतरराष्ट्रीय रोजगार परामर्श, कौशल प्रमाणन, विदेश प्रस्थान से पूर्व अभिमुखीकरण और सुरक्षित प्रवासन संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बिहार के युवाओं को न केवल बेहतर वेतन वाले अंतरराष्ट्रीय रोजगार मिल सकेंगे, बल्कि वे सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से वैश्विक श्रम बाजार का हिस्सा भी बन सकेंगे।

उद्योग की मांग के अनुरूप तैयार होगा कार्यबल

एसआईआईसी केवल भाषा प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहेगा। यह केंद्र विद्युत सेवाओं, प्लंबिंग, निर्माण, कृषि तथा अन्य उच्च मांग वाले व्यवसायों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इन पाठ्यक्रमों को उन देशों की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा, जहां भारतीय कुशल श्रमिकों की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं की रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और बिहार वैश्विक कौशल आपूर्ति श्रृंखला में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकेगा।■

भविष्य की ओर बढ़ता बिहार

आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में वही समाज आगे बढ़ रहा है, जो अपने मानव संसाधन में निवेश कर रहा है। बिहार ने भी इस दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा दिया है। आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान, अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र, उभरती तकनीकों पर आधारित पाठ्यक्रम और वैश्विक रोजगार से जुड़ा तंत्र राज्य के युवाओं को नई पहचान देने की क्षमता रखते हैं। आने वाले वर्षों में जब बिहटा का आधुनिक कौशल परिसर पूरी तरह संचालित होगा और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हजारों युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ेगा, तब बिहार की पहचान केवल प्रतिभाशाली युवाओं के राज्य के रूप में नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय कुशल कार्यबल तैयार करने वाले अग्रणी राज्य के रूप में भी स्थापित होगी। यही पहल 'विकसित भारत' के उस विजन को मजबूत करेगी, जिसमें हर युवा के पास कौशल, अवसर और सम्मानजनक रोजगार का मार्ग उपलब्ध हो।

हॉकी टीम की केसरिया जर्सी का विवाद बेवजह

हॉकी की पुरुष और महिला टीमें विश्व कप से नीली की बजाय केसरिया जर्सी में खेलेंगी

पहले भी कई बार बदल चुका है हॉकी टीम की ड्रेस का रंग

सत्येन्द्र पाल सिंह

भारतीय हॉकी टीमों की जर्सी नीले से केसरिया रंग करने पर सवाल उठ रहे हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की का पहले जर्सी का रंग केसरिया करने का समर्थन करना और फिर इससे पलटना यह साफ जताता है कि यह विवाद बेकार है। इस मामले पर चाहे बीजेडी हो या कांग्रेस, सभी भारतीय हॉकी टीम की जर्सी नीले से केसरिया करने पर राजनीति ही कर रहे हैं। चाहे वह दिलीप तिर्की हों या परगट सिंह, अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते उन्हें परेशानी केसरिया रंग से है।

बेशक भारतीय हॉकी टीम (पुरुष एवं महिला दोनों) लंबे समय तक नीली जर्सी में खेली है, लेकिन कई मौकों पर वह पीली व अन्य रंग की जर्सी में भी कई बड़े टूर्नामेंटों में खेली है। अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम सफेद और केसरिया जर्सी में खेली है। इसी कारण पहले टीम के लिए केसरिया जर्सी पर रजामंदी जताने के बाद दिलीप तिर्की का हॉकी इंडिया कार्यकारिणी से जर्सी बदलने की बाबत मेल कर सवाल पूछना उलटे उन्हें ही कटघरे में खड़ा करता है। दिलीप तिर्की के साथ पूर्व हॉकी कप्तान ओलंपियन परगट सिंह, वासुदेवन भास्करण, धनराज पिल्लै और वीरेन रसकिन्हा ने भी हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदल कर केसरिया करने की आलोचना की है।

दिलीप तिर्की ने अपना बयान और रुख अपनी पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष नवीन पटनायक के जर्सी का रंग बदलने की आलोचना करने के बाद ही बदला है। रही बात परगट सिंह की, तो वह कांग्रेस के एमएलए हैं और उन्हें भी अपनी पार्टी का ही समर्थन करना है। इसके उलट पूर्व हॉकी

ओलंपियन व कप्तान जगबीर सिंह और पीआर श्रीजेश ने कहा कि जर्सी के रंग को लेकर बेवजह विवाद को दरकिनार इस समय ध्यान हॉकी विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर लगाना चाहिए।

दिलीप तिर्की अपने जिस ई-मेल से सुर्खियों में बने वह कैसे अखबारों और न्यूज चैनलों तक पहुंचा या पहुंचाया गया, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तिर्की के ई-मेल के जवाब में हॉकी इंडिया ने एक बयान जारी कर जवाब देते हुए कहा, 'भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने का फैसला सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों की सिफारिशों और उनसे बातचीत के बाद लिया गया था।'

पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, 'जर्सी का रंग बदलने को विवाद का नाम क्यों दिया जा रहा है? पहली बार भारतीय टीम की जर्सी का रंग नहीं बदला गया है। इसे पहले भी बदला जा चुका है। जब हम सभी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ ने आपस में बैठ कर जर्सी का रंग बदलने पर चर्चा की और फिर केसरिया पर सहमति बनी तो फिर इस पर विवाद बेवजह है। सभी को ध्यान सिर्फ और सिर्फ आगामी हॉकी विश्व कप पर लगाना चाहिए। सभी को हमारा समर्थन करना चाहिए। इस पर विवाद क्यों?'

जब भारतीय हॉकी टीमों की जर्सी का रंग बदल कर केसरिया किया गया, तब दिलीप तिर्की ने कहा, 'भारतीय हॉकी टीम बरसों से नीली जर्सी पहन कर कई अहम टूर्नामेंट खेलती रही है। मैं खुद भी भारत के लिए खूब नीले रंग की जर्सी पहन कर खेला हूं। भारतीय टीम की जर्सी के रंग में बदलाव पहली बार नहीं हो रहा है। 2014 में हमारी टीम ने पीली और 2018 में हल्के नीले रंग की जर्सी का इस्तेमाल किया। जर्सी का रंग बदलने का यह सुझाव सीधे हमारे कोच, सपोर्ट स्टाफ, खिलाड़ियों और कप्तानों की ओर से आया था। टीम के कोच और खिलाड़ियों को लगा कि नीले एस्ट्रो टर्फ पर नीली जर्सी पहनने से उन्हें तकनीकी रूप से साथी खिलाड़ियों को टर्फ पर पहचानने में दिक्कत आ रही थी। टीम ने जो दो रंग सुझाए थे, वे थे पीला और केसरिया। केसरिया रंग क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में भी शामिल है और इसीलिए हमने जर्सी के लिए केसरिया चुना है। अगर विश्व कप के दौरान खिलाड़ियों को केसरिया रंग के साथ सहज महसूस नहीं होता है, तो हम भविष्य में इसे बदल सकते हैं।'

बेशक भारतीय हॉकी टीम (पुरुष एवं महिला दोनों) लंबे समय तक नीली जर्सी में खेली है, लेकिन कई मौकों पर वह पीली व अन्य रंग की जर्सी में भी कई बड़े टूर्नामेंटों में खेली है। अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम सफेद और केसरिया जर्सी में खेली है। इसी कारण पहले टीम के लिए केसरिया जर्सी पर रजामंदी जताने के बाद दिलीप तिर्की का हॉकी इंडिया कार्यकारिणी से जर्सी बदलने की बाबत मेल कर सवाल पूछना उलटे उन्हें ही कटघरे में खड़ा करता है।

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जर्सी का रंग बदलने को भारतीय हॉकी की विरासत पर हमला बताया। पटनायक ने कहा, 'भारतीय हॉकी टीम का प्रतिष्ठित नीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है। यह राष्ट्र की खेल विरासत से जुड़ी एक भावना है। हॉकी टीम की जर्सी में यह बदलाव ओडिशा में भाजपा सरकार के दबाव में किया गया।'

भारत के पूर्व हॉकी ओलंपियन जगबीर सिंह कहते हैं, 'भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदल केसरिया किए जाने के विवाद का हॉकी विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है। जर्सी का रंग पहली बार नहीं बदला गया है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे खिलाड़ी इतने अनुभवी हैं कि वे इस तरह के विवादों को दरकिनार कर हॉकी विश्व कप जैसे बड़े मंच पर बढ़िया प्रदर्शन का दम रखते हैं।' हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब खिलाड़ी देश के लिए मैदान पर खेलने उतरता है तो उसकी जर्सी का रंग कोई भी हो वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। मौजूदा खिलाड़ियों की ताकत भी यही है कि वे सब कुछ भुला कर देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे। नीले रंग से नीली टर्फ पर खिलाड़ियों को साथी को देखने में कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी। अब नीली हॉकी टर्फ पर बेशक केसरिया रंग से साथी खिलाड़ी टर्फ पर बेहतर दिखेगा। पैडी अपटन जैसे मेंटल कंडीशनिंग कोच की मौजूदगी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने जेहन से किसी भी तरह की नकारात्मकता को निकालकर पूरी तरह एकाग्र होकर हॉकी विश्व कप 2026 में खेलेगी। यही कामना है कि भारतीय टीम नई जर्सी में इतना यादगार प्रदर्शन करे कि आने वाली पीढ़ी में इस नई जर्सी में भारत के लिए हॉकी खेलने की होड़ लग जाए।

भारतीय हॉकी टीम के पूर्व ओलंपियन गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कहा, 'मुझे भारतीय हॉकी टीम के केसरिया जर्सी पहनने से कोई ऐतराज नहीं है। अब हमारी टीम को बाहरी बातों पर ध्यान न देकर अपना ध्यान केवल हॉकी विश्व कप पर लगाना चाहिए। भारत ने 2014 और 2018 विश्व कप के दौरान अलग-अलग रंगों की किट पहनी थी। तब इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। अब भारतीय खिलाड़ियों को केसरिया रंग की जर्सी मान्य है तो बहस यही खत्म हो जानी चाहिए।' ■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

गोबर से स्वच्छ ऊर्जा बनाने को एमसीडी-एनडीबीबी में एमओयू

पशुपालकों की आय और यमुना की सफाई को मिलेगा बल

युवा सहकार टीम

राजधानी में पशुओं के गोबर का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उससे स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद बनाने की दिशा में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीबीबी) ने महत्वपूर्ण पहल की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों संस्थाओं ने दिल्ली में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य डेयरियों और गोशालाओं से निकलने वाले गोबर को नदियों, नालों और खुले स्थानों में जाने से रोककर उपयोगी संसाधन में बदलना है।

समझौते के तहत दिल्ली के नांगली, घोघा-गोयला और गाजीपुर स्थित अपशिष्ट निस्तारण केंद्रों पर गोबर के प्रसंस्करण की व्यवस्था विकसित की जाएगी। डेयरियों और गोशालाओं से गोबर एकत्र कर इन संयंत्रों तक पहुंचाया जाएगा, जहां इससे कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन होगा। दिल्ली में करीब 1.25 लाख मवेशियों से निकलने वाले अपशिष्ट का उचित निस्तारण शहरी स्वच्छता और यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।

परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पशुपालकों को गोबर का आर्थिक मूल्य दिलाना है। समझौते में पशुपालकों को एक रुपये प्रति किलोग्राम गोबर का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। अभी तक जिस गोबर को अपशिष्ट और समस्या के रूप में देखा जाता था, वह अब पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकेगा। नियमित संग्रह व्यवस्था विकसित होने से पशुपालकों को पशुओं के अपशिष्ट के निस्तारण की समस्या से भी राहत मिलेगी।

कंप्रेस्ड बायोगैस का उपयोग स्वच्छ परिवहन और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। गोबर से गैस निकालने के बाद बचने वाली जैव-स्लरी को प्रसंस्कृत कर जैविक खाद तैयार की जा सकती है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने, मिट्टी की सेहत सुधारने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। एनडीडीबी पहले से विभिन्न राज्यों में घरेलू, सामुदायिक और बड़े स्तर के बायोगैस मॉडल विकसित कर रहा है, जिनमें पशुपालकों को ऊर्जा, जैविक खाद और अतिरिक्त आय से जोड़ने पर जोर दिया जाता है

इस पहल को यमुना की सफाई से भी जोड़ा गया है। डेयरी अपशिष्ट और गोबर नालों के माध्यम से नदी में पहुंचकर प्रदूषण बढ़ाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में गोबर की थोड़ी मात्रा भी यमुना में न जाए। दिल्ली में सीवर और औद्योगिक अपशिष्ट के शोधन के लिए लगभग 80 उपचार संयंत्रों पर काम शुरू होने की जानकारी भी दी गई है। सरकार ने दिसंबर 2028 तक यमुना में गंदे पानी का प्रवाह रोकने का लक्ष्य रखा है।

अमित शाह ने इस समझौते को देश के अन्य बड़े शहरों के लिए संभावित मॉडल बताया है। महानगरों में डेयरी अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था विकसित होने से एक साथ कई लाभ मिल सकते हैं। शहरों की सफाई सुधरेगी, नदियों और नालों का प्रदूषण कम होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी।

एमसीडी और एनडीबीबी की यह साझेदारी सहकारिता, स्वच्छता और हरित ऊर्जा को एक साथ जोड़ने वाली सर्कुलर इकोनॉमी का उदाहरण है। प्रभावी गोबर संग्रह, समय पर भुगतान और संयंत्रों के नियमित संचालन के साथ यह परियोजना दिल्ली में डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन की तस्वीर बदल सकती है तथा देश के अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए भी अनुकरणीय व्यवस्था बन सकती है।■

INDRAPRASTHA GAS

Leading India's clean energy landscape

IGL believes in a customer-centric approach and provides clean energy solutions through innovative technology and diversification in India and abroad. IGL is playing a crucial role in the emerging scenario, in augmenting its compression capacity by adding new stations and investing in new-age fuels like Liquefied Natural Gas (LNG), Compressed Bio Gas (CBG) and Solar to address changing energy needs.

IGL's core deliverables include:

- IGL is a leading provider of clean and convenient Piped Natural Gas (PNG) and Compressed Natural Gas (CNG).
- IGL offers various services to meet the needs of Residential, Commercial and Industrial customers.
- IGL is a growing company, strongly committed to safety, innovation, and customer satisfaction.

Customer Care
1800 102 5109 / 1800 180 5109 (24x7 Toll Free)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
An ISO 9001, ISO 14001 & OHSMS 45001 Certified Company
CIN No.: L23201DL1998PLC097614
World Trade Centre, Block G, 2nd Floor, Nauroji Nagar,
New Delhi-110029, Website: www.iglonline.net
Follow us:

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF EDUCATION
Government of India
सत्यमेव जयते

nbt.india
एकः सूते सकलम्

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
की
स्वतंत्रता संग्राम विषयक पुस्तकें

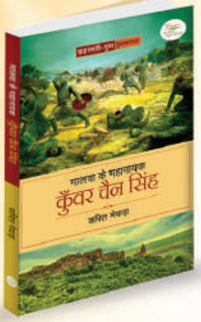

मालवा के महानायक : कुँवर चैन सिंह
कपिल मेवाड़ा
पृष्ठ 122 | मूल्य : रु. 190

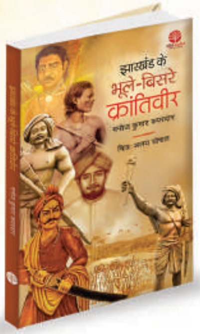

झारखंड के भूले-बिसरे क्रांतिकारी
मनोज कुमार कपरदार
पृष्ठ 132 | मूल्य : रु. 100

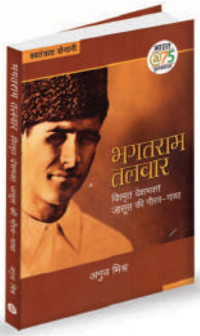

भगतराम तलवार : विस्मृत देशभक्त जासूस की गौरव-गाथा
अनुज मिश्र
पृष्ठ 171 | मूल्य : रु. 245

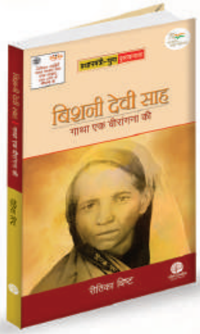

बिशनी देवी साह : गाथा एक वीरांगना की
रीतिका बिष्ट
पृष्ठ 70 | मूल्य : रु. 130

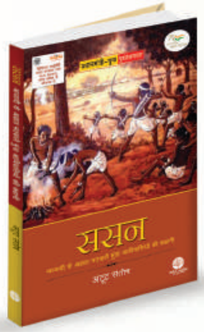

ससन : आजादी के अज्ञात मतवाले मुंडा आदिवासियों की कहानी
अटूट संतोष
पृष्ठ 92 | मूल्य : रु. 155

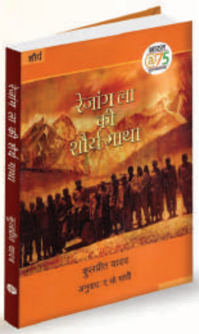

रेजांग ला की शौर्य गाथा
कुलप्रीत यादव
अनुवाद : ए.के. गाँधी
पृष्ठ 185 | मूल्य : रु. 290

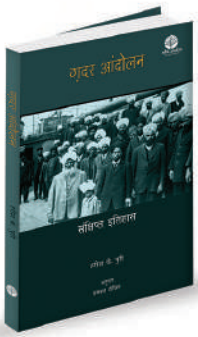

ग़दर आंदोलन : संक्षिप्त इतिहास
हरीश के. पुरी
पृष्ठ 160 | मूल्य : रु. 150

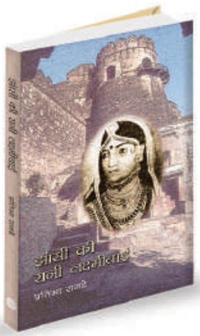

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
प्रतिभा रानडे
अनुवाद : गोविंद गुंठे
पृष्ठ 224 | मूल्य : रु. 235

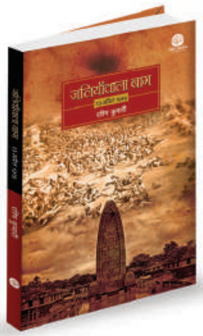

जलियाँवाला बाग : 13 अप्रैल 1919
रश्मि कुमारी
पृष्ठ 130 | मूल्य : रु. 165

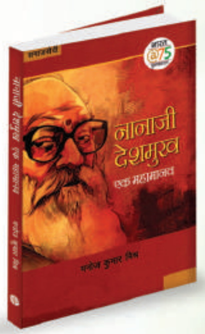

नानाजी देशमुख : एक महामानव
मनोज कुमार मिश्र
पृष्ठ 99 | मूल्य : रु. 165

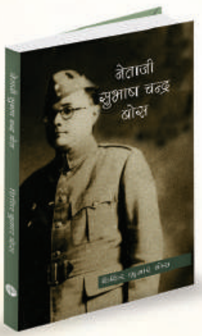

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
शिशिर कुमार बोस
पृष्ठ 140 | मूल्य : रु. 145

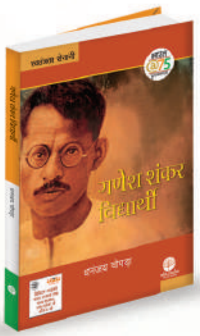

गणेश शंकर विद्यार्थी
धनंजय चोपड़ा
पृष्ठ 174 | मूल्य : रु. 240

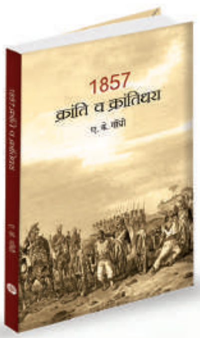

1857 : क्रांति व क्रांतिधरा
ए. के. गाँधी
पृष्ठ 100 | मूल्य : रु. 130

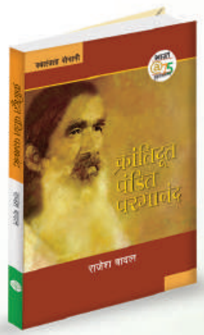

क्रांतिदूत पंडित परमानंद
राजेश बादल
पृष्ठ 167 | मूल्य : रु. 245

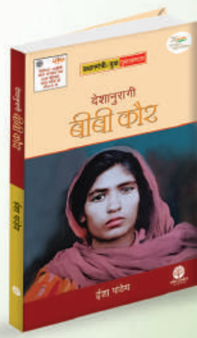

देशानुरागी : बीबी कौर
ईशा पांडेय
पृष्ठ 88 | मूल्य : रु. 150

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
Ministry of Education, Government of India

5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
ईमेल : office.nbt@nic.in | वेबसाइट : www.nbtindia.gov.in